R.N.I. : UPHIN/2012/52437
Website : www.mantrabharat.com
संस्करण : प्रयागराज
वर्ष : 15
अंक : 15
पृष्ठ : 8
मूल्य : 1.00
मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

डाक पंजीयन संख्या : एल-2/9/रजि0/ए0डी0/119/15-17

प्रयागराज, लखनऊ, ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़ व गोरखपुर से प्रसारित

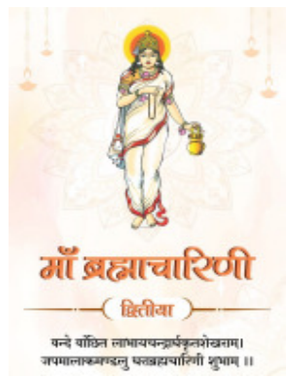

3 घटी जीएसटी के स्लैब को लेकर फायदे बताएंगे भाजपाई 5 पोषण भी-पढ़ाई भी' एवं राष्ट्रीय पोषण माह ... 7 नवरात्रि के पहले दिन 'मर्दानी 3' का ऐलान

जीएसटी कटौती का लाभ जनता को मिल रहा या नहीं, जानने बाजार पहुंचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

पटना **(एजेंसी)**। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जीएसटी बचत उत्सव के मौके पर आमजनों से मिलने के लिए पहुंचे। 22 सितंबर से टैक्स स्लैब में हुए बदलाव के बाद उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी राजधानी पटना के दुकानों और मोटरसाइकिल शोरूमों में पहुंचे। चौधरी यहां यह जानने के लिए पहुंचे कि जीएसटी दरों में आई कटौती से आम उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है या नहीं। श्रीकृष्णा पुरी स्थित सुपर स्टोर में उन्होंने स्टोर मैनेजर से बातचीत कर मूल्य में आई कमी और खरीदारी पर पड़े असर की जानकारी ली।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी की नई दरों से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, वहीं मोटरसाइकिल खरीद पर 6 हजार से लेकर 13 हजार रुपये तक का सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की कि वे इस राहत का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। चौधरी ने कहा- कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटने का काम किया और आम आदमी को कभी फायदा नहीं पहुंचाया। इसके विपरीत मोदी सरकार लगातार आम आदमी को, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुविधाएं दे रही है।

त्योहारों के इस मौसम में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरित की जा रही है। सम्राट चौधरी ने बताया कि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75 लाख बहनों के खाते में धनराशि उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा नवरात्र, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व से पहले जीएसटी में रियायत और खातों में सीधी मदद से ही लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी और त्यौहार का आनंद दोगुना होगा।

दशहरा उद्घाटन पर सियासत! सिद्धारमैया ने विरोधियों को घेरा, कहा- दशहरा किसी एक धर्म का त्योहार नहीं है

बेंगलुरु **(एजेंसी)**। बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक द्वारा मैसूर दशहरा 2025 के उद्घाटन और कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उठाई गई कई आपत्तियों के बाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि दशहरा राज्य के सभी लोगों का त्योहार है; यह किसी एक धर्म या जाति का त्योहार नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बानू मुश्ताक, एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद, एक कन्नड़ कवि और लेखिका हैं। उन्होंने कन्नड़ साहित्य को सम्मान दिलाया है। परंपरा के अनुसार, इस वर्ष दशहरा 11 दिनों तक मनाया जा रहा है। राज्य में अच्छी बारिश हुई है और लोग मुस्कुरा रहे हैं। जंबू सवारी की विशेष भव्यता होगी। गारंटी योजनाएँ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं की जाती हैं।

सिद्धारमैया ने सवाल किया कि क्या भाजपा या जद (एस) इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं? ये योजनाएँ सभी लोगों के लिए हैं। कन्नड़ कवि कुवेम्पु ने कहा कि व्यक्ति को मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदों से ऊपर उठना चाहिए। समाज को धर्म या जाति के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। दशहरा राज्य के सभी लोगों का त्योहार है। यह किसी एक धर्म या जाति का त्योहार नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं का समर्थन किया और विपक्ष से पूछा कि क्या राज्य दिवालिया हो गया है।

सिद्धारमैया ने कहा कि कुछ लोगों ने चेतावनी दी थी कि गारंटी योजनाओं को जारी रखने से राज्य दिवालिया हो जाएगा। क्या राज्य दिवालिया हो गया है? अब तक, हमने अपनी गारंटी योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति को लाभ हुआ है। जो लोग पहले इन योजनाओं का विरोध करते थे, वे अब इनकी नकल कर रहे हैं। कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के मामले में, कर्नाटक देश में नंबर एक है। गारंटी योजनाओं ने सभी लोगों की आय में वृद्धि की है। बानू मुश्ताक ने पूरे अर्थ के साथ बात की। उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने उनका विरोध किया था, वे भी दिल से प्रसन्न होंगे।'

इससे पहले, बानू मुश्ताक ने सोमवार को चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में मैसूर दशहरा का उद्घाटन किया। मुश्ताक ने कहा कि हम आज माँ चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद से दशहरा उत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं। एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा था कि वह मुझे चामुंडी पहाड़ियों पर ले जाएगी, लेकिन आज, माँ चामुंडेश्वरी ने खुद मुझे यहाँ बुलाया है। भले ही कुछ विरोध व्यक्त किया गया था, माँ ने मुझे बुलाया है। उनकी कृपा के तहत यहाँ खड़ा होना मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है।

गोवा नए जीएसटी सुधारों के जरिये एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध : सावंत

पणजी **(एजेंसी)**। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों का स्वागत किया और कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर भारत 2.0 की दिशा में देश की यात्रा को और मजबूत करेगी। सावंत ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों से सूक्ष्म, लघु एवं मझाले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और 'वोकल फॉर लोकल, थिंक ग्लोबल' के दृष्टिकोण के साथ विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, '' गोवा इस अभियान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है... बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, प्रक्रियाओं को सरल बनाना एवं हमारे उद्यमियों को सशक्त बनाना ताकि स्वदेशी उत्पाद भारत और दुनिया भर में गर्व से अपनी पहचान बना सकें।'' प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा था कि सोमवार से लागू होने वाले जीएसटी सुधार देश की वृद्धि दर को और बढ़ाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलने से देश में समृद्धि बढ़ेगी।

त्रिपुरेश्वरी मंदिर से अरुणाचल प्रदेश की बिजली परियोजनाओं तक, पूर्वोत्तर को मोदी के दौरे से मिली नई ऊर्जा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक देश की राजनीतिक और विकासात्मक मुख्यधारा से दूरी का अनुभव करता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की पहचान बदल रही है और इस बदलाव की धुरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विशेष रणनीति। उनकी त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की आज की यात्राएं केवल कार्यक्रम भर नहीं थीं, बल्कि पूर्वोत्तर की नई दिशा और दशा का संदेश थीं। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा के गोमती ज़िले में प्रधानमंत्री ने 500 वर्ष पुराने त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की। गर्मी के बीच, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग मंदिर के बाहर जमा हुए थे। पांच सौ वर्ष से भी अधिक पुराना यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का केंद्र सरकार की 'प्रसाद' या पीआरएएसएडी (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान) योजना के तहत 52 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। हम आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा धन्य माणिक्य ने 1501 में करवाया था। केंद्र सरकार की योजना के तहत 52 करोड़ रुपये की लागत से हुए जीर्णोद्धार ने इस शक्ति पीठ को नई ऊर्जा दी है। यह केवल एक धार्मिक स्थल का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय रोज़गार सृजन का ठोस प्रयास है। यह कदम बताता है कि मोदी सरकार विकास की धारा में स्थानीय आस्था और परंपरा को बराबर का स्थान देना चाहती है।

वहीं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने 5, 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की नींव रखी। इसमें तातो-1 और हीओ जैसी बड़ी पनबिजली परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे अरुणाचल प्रदेश भारत का बिजली उत्पादन केंद्र बनने की ओर बढ़ेगा। तवांग में बनने वाला सम्मेलन केंद्र पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को गति देगा। इसके अलावा कैंसर संस्थान, नई सड़कें, महिला छात्रावास और अग्निशमन केंद्र जैसी परियोजनाएं सीधे जनता के जीवन स्तर को छूती हैं। मोदी ने कहा कि यह सब 'डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट' का उदाहरण है।

हम आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से आज पूर्वोत्तर में सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक, ऊर्जा से लेकर शिक्षा तक, हर क्षेत्र में काम की गति तेज हुई है। परिणामस्वरूप यह इलाका अब पिछड़ेपन के बजाय अवसरों की नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है।

देखा जाये तो त्रिपुरा और अरुणाचल की ये यात्राएं यह स्पष्ट करती हैं कि पूर्वोत्तर अब सिर्फ़ सीमावर्ती भूगोल नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का नया इंजन है। धार्मिक धरोहर की रक्षा और आधुनिक अवसंरचना का निर्माण, दोनों को समान महत्व देकर मोदी सरकार इस क्षेत्र को 'भारत के उदयमान पूर्व' के रूप में गढ़ रही है। बहरहाल, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्वोत्तर में अब एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है– जहाँ परंपरा भी सुरक्षित है और विकास भी सुनिश्चित।

ओम प्रकाश राजभर अभी भी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को चक्कर आने और चलने में दिक्कत की शिकायत पर उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी सेहत में पहले से काफी सुधार है। मेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉ राकेश कपूर के मुताबिक राजभर को माइनर स्ट्रोक की समस्या है। दरअसल, ओम प्रकाश राजभर की बीते रविवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक उन्हें लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। इस बीच देर शाम को उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने आनन-फानन में उनका सिटी स्कैन, खून समेत कई जांचें कराई गईं। जांच के दौरान स्ट्रोक का मामला सामने आने पर उनका इलाज न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की देख रेख में चल रहा है। मेदान्ता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर का स्वास्थ्य पहले से सुधार है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। वहीं राजभर के मेंदाता अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी सोशल मीडिया फेसबुक के जरिये देते हुए उनके बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने कहा ' मंत्री ओमप्रकाश राजभर को अस्वस्थता के कारण मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं से उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है।'

नामुमकिन को मुमकिन बनाने का माद्दा रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग सहित दुनिया के तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोदी नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। प्रधानमंत्री के भाषणों की दो पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बावजूद, ट्रंप ने हमेशा मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसी तरह ''अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मतभेदों के बावजूद'' चीनी राष्ट्रपति के भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं।

उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राधाकृष्णन ने कहा, ''अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, लेकिन ट्रंप हमेशा कहते हैं कि मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं मोदी के खिलाफ हूं। वह हमेशा कहते हैं कि मैं मोदी के साथ हूं।'' राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति (व्लादिमीर) पुतिन के भी बेहद अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा, ''...साथ ही, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मतभेदों के बावजूद, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी मोदी जी के अच्छे मित्र हैं। यह हमने आज देखा है।''

उपराष्ट्रपति ने कहा, ''यही कारण है कि वह (प्रधानमंत्री मोदी) नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं।'' मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के लिए सच्चे मन से काम करते हैं और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते।

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता की भाषा बोलते हैं और उन्हीं के लिए बोलते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले जब सरकारी योजनाएं शुरू होती थीं, तो वे 'बैंड-एड' (केवल तुरंत राहत) की तरह काम करती थीं। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों की सोच बदल दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी राजनीति का इस्तेमाल जनसेवा के लिए करते हैं और उनका हर फैसला समाज की भलाई को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

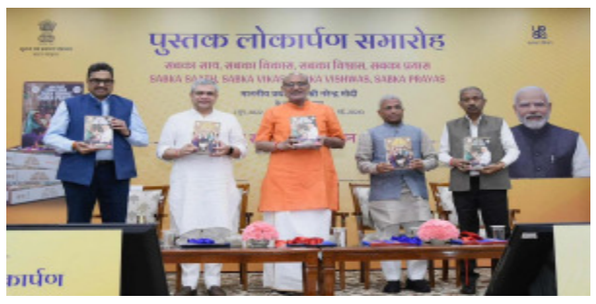

राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को दूरसंचार अधिकारी बनकर ठगने का प्रयास, मामला दर्ज

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। राज्यसभा सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति हाल ही में एक धोखाधड़ी वाली कॉल का शिकार हुईं, जिसमें उनसे संवेदनशील निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। 20 सितंबर को बेंगलुरु साइबर पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में, मूर्ति ने 5 सितंबर की सुबह हुई इस घटना का विवरण साझा किया। उनके बयान के अनुसार, उन्हें एक नंबर से कॉल आया, जिसे ट्रूकॉलर ऐप पर चेक करने पर दूरसंचार विभाग का नंबर लगा। कॉल करने वाली महिला ने खुद को दूरसंचार मंत्रालय की कर्मचारी बताया। महिला ने कहा कि मूर्ति का मोबाइल नंबर जनवरी 2020 में उसके आधार से लिंक किए बिना ही रजिस्टर कर लिया गया था। उसने मूर्ति पर उस नंबर का इस्तेमाल अश्लील वीडियो देखने या वितरित करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि उसी दिन दोपहर 12 बजे तक उसकी मोबाइल सेवाएँ बंद कर दी जाएँगी।

इसके बाद, कॉल करने वाले ने मूर्ति से संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जब मूर्ति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो कॉल करने वाले ने गाली-गलौज की और धमकियाँ दीं। इस बीच, बेंगलुरु में साइबर अपराध पुलिस में इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुधा मूर्ति ने धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश करने और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में कॉल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुधा मूर्ति एक भारतीय लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और परोपकारी हैं, जिन्हें शिक्षा और ग्रामीण विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। 1950 में जन्मी, वह इंफोसिस टेक्नोलॉजीज की परोपकारी शाखा, इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं।

सुधा मूर्ति ने अंग्रेजी और कन्नड़ में उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और बाल साहित्य सहित कई किताबें लिखी हैं और अपनी सरल लेकिन प्रभावशाली कहानी कहने की कला के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। विभिन्न सामाजिक पहलों, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति उनके समर्पण के लिए उन्हें सराहा जाता है। उनके काम और विनम्रता ने उन्हें भारत और विदेशों में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है।

बिहार को मिली 9400 करोड़ की सौगात!

सीएम ने किया जेपी गंगा पथ समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास

पटना **(एजेंसी)**। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिला के दीघा में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 6495 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से पटना जिला अंतर्गत दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ) तक जे0पी0 गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण (लंबाई-35.65 कि0मी0) कार्य का शिलान्यास किया। जे0पी0 गंगापथ परियोजना के विस्तारीकरण कार्य पूर्ण होने से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ (एन0एच0-922) तथा लखनऊ-गाजीपुर के बीच निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ (एन0एच0-319) से सम्पर्कता मिलेगी। साथ ही दानापुर-छितनावां-मनेर पथ (पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30) पर लगनेवाली जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना आने-जाने में भी काफी सहूलियत होगी। साथ ही बिहटा हवाई अड्डा आने-जाने में सुविधा होगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जे0पी0 गंगापथ का कोईलवर तक विस्तारीकरण कार्य आज से शुरू हो गया है। निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूर्ण करें। इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने से शहरवासियों को आवागमन में और सहूलियत होगी।

मुख्यमंत्री ने दीघा से ही विभिन्न जिलों के 5 अन्य पथों जिनकी कुल लम्बाई 225.475 किलोमीटर है तथा जिनकी लागत 2 हजार 900 करोड़ रुपये है, का भी शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत 650 करोड़ 51 लाख की लागत से बांका, मुंगेर एवं भागलपुर जिला अंतर्गत धोरैया-इंगलिस मोड़ असरगंज पथ (लंबाई 58.47 कि0मी0) का निर्माण कार्य, 814 करोड़ 22 लाख की लागत से मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत हथौड़ी-औराई पथ में एक उच्च स्तरीय पुल (लंबाई- 21.3 कि0मी0) का पहुंच पथ सहित निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। साथ ही 373 करोड़ 56 लाख की लागत से भोजपुर जिला अंतर्गत आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ (लंबाई 32.26 कि0मी0) के निर्माण कार्य, 701 करोड़ 26 लाख की लागत से छपरा एवं सीवान जिला अंतर्गत छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ (लंबाई-72.18 कि0मी0) के निर्माण कार्य तथा 361 करोड़ 32 लाख की लागत से नवादा, नालंदा एवं गयाजी जिला अंतर्गत बनगंगा-जेठियन-गहलौत बिन्दस पथ (लंबाई 41.25 कि0मी0) के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर0 पुडुकलकट्टी, पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ0 चंद्रशेखर सिंह, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एस0एम0, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के0 शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सरकार ने पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर जो वसूली की है, क्या वह जनता को नकद दी जाएगी : अखिलेश यादव

लखनऊ **(एजेंसी)**। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि सरकार ने पिछले आठ सालों में जीएसटी के नाम पर जो वसूली की है, क्या वह जनता को नकद दी जाएगी। सपा प्रमुख ने जीएसटी संग्रह को लेकर जनता के हवाले से सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने जीएसटी की धनराशि लौटाने के लिए दस सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक 'एक्स' खाते पर रविवार देर रात एक पोस्ट में कहा 'जनता पूछ रही है भाजपा सरकार ने पिछले आठ सालों में जो वसूली जीएसटी के नाम पर की है, वो कुल राशि उप्र भाजपा सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा 'घर' पर 'कैश' पहुंचाई जाएगी।' यादव ने आगे पूछा, ?'या बीमे के अगले प्रीमियम में एडजस्ट की जायेगी? या डाइरेक्ट बेनेफ़िट के माध्यम से खातों में सीधे (खाते में) वापस आ जाएगी? ?या भाजपाइयों के ऊपर वादे का जो पंद्रह लाख बचा है, उसमें से घटाई जाएगी?' सवालों की कड़ी में सपा प्रमुख ने पूछा, ?या होली-दीवाली के बहुत दिनों से लंबित पड़े सिलेंडरों के आश्वासन के साथ दो किस्तों में दी जाएगी? या कंपनियों से भाजपा को पिछले दरवाज़े से मिली राशि से चुकता की जाएगी? सपा प्रमुख ने कहा कि या ये रक़म भाजपाई नेताओं के द्वारा अगले चुनाव की पूर्व संध्या पर द्रव्य रूप में बांटी जाएगी? ?या बच्चों की फ़ीस न लेकर पूरी की जाएगी? या इसकी क्षतिपूर्ति बीमारों और बुजुर्गों की दवा-देखभाल को निःशुल्क घोषित करके की जाएगी? उन्होंने आखरि में पूछा कि 'या भाजपा के जुमलाकोश में जोड़ दी जाएगी?'

मुविवि में वर्तमान युग में भारतीय ज्ञान परम्परा की उपादेयता पर संगोष्ठी

आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें - कुलपति

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के मानविकी विद्याशाखा के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जन्मोत्सव पखवाड़े के अन्तर्गत वर्तमान युग में भारतीय ज्ञान-परम्परा की उपादेयता विषय पर एक वेबिनार/सेमिनार का आयोजन सोमवार को विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित तिलक शास्त्रार्थ सभागार में किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विश्वविद्यालय एवं शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना आत्मनिर्भर भारत बनाने के परिप्रेक्ष्य में लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षार्थियों को कौशलपरक व स्वरोजगार परक शिक्षा देने के लिए आग्रह किया। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने विश्वविद्यालय की सभी विद्याशाखाओं से आग्रह किया कि वे अपने पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परम्परा का एक अध्याय निश्चित रूप से जोड़ें, जिससे हमारे शिक्षार्थी आधारभूत ज्ञान से परिचित हो सकें। उन्होंने शिक्षार्थियों के स्वावलंबी बनने पर जोर दिया। जिसके लिए उन्हें लघु उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जानने की आवश्यकता है। अतीत के ज्ञान से भविष्य का निर्माण होता है। वैदिक वांङमय, उपनिषद, पुराण, आगम और तंत्र भाषा विज्ञान, संस्कृत, काव्य भाषाओं का साहित्य, आधुनिक भारतीय साहित्य भारतीय ज्ञान परम्परा के श्रोत है। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा जीवन के सभी पहलुओं शारीरिक, मानसिक, नैतिक और

आध्यात्मिकता को समग्र रूप से देखती है, जो एक संतुलित और परिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। यह परम्परा नैतिक मूल्यों सह-अस्तित्व और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है जो आधुनिक भौतिकवाद और नैतिक क्षरण का प्रतिकार करती है। यह अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहायक है और लोगों को अपनी पहचान और मूल्यों को बनाये रखने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय उपनिषद् भारतीय दर्शन का मूल स्रोत हैं। सभी तत्वों का समावेश है उन्होंने रामायण एवं महाभारत जैसे आदि काव्यों में उल्लेखित आदर्शों एवं मूल्यों पर चिन्तन पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अरविन्द नारायण मिश्रा, शिक्षा शास्त्र विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा में ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाया और सम्पूर्ण जीवन को समाज और सनातन को समर्पित किया। भारत पर आक्रान्ताओं ने उनकी चिन्तन धारा और ज्ञान गंगा को दबाने और पीछे करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के बाद विशेष कर विगत कुछ वर्षों से भारतीय ज्ञान परम्परा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोफेसर मिश्र ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा के जनक ऋषियों ने अपने त्याग और समर्पण से लोक हित में चिन्तन आदर्शों और मूल्यों को स्थापित किया है। भारतीय ज्ञान परम्परा सामाजिक सदभाव, समरसता, पर्यावरण, संस्कृति, संस्कार आदि के भाव को शिखर पर पहुँचाते हैं।

कार्यक्रम के निदेशक प्रोफेसर सत्यपाल तिवारी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा की उपादेयता केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की उपादेयता सिद्ध कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने तपस्या, जीवन पद्धति से विश्व का मार्गदर्शन किया। भारतीय ज्ञान परम्परा शोध और सिद्धान्तों की जनक रही है। भारतीय ज्ञान परम्परा शांतिप्रिय रही है। हमारे मूल्य युद्ध नहीं चाहते थे। वेबिनार/सेमिनार के समन्वयक प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्त ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रर्वतन करते हुए कहा कि आज का सामाजिक विखण्डन, पर्यावरणीय संकट आदि के सन्दर्भ में भारतीय ज्ञान परम्परा में अनेक समाधान प्रस्तुत किये गये हैं। जो आज उपादेय सिद्ध हो सकते हैं। इस अवसर पर शोध छात्राओं द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन शोध छात्र संस्कृत दिग्विजय सिंह ने तथा आयोजन सचिव डॉ. अतुल कुमार मिश्र ने आभार व्यक्त किया। सह आयोजन सचिव डा. दयानन्द उपाध्याय तथा संजीव भट्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर समस्त विद्याशाखाओं के निदेशक, आचार्यगण, सह-आचार्यगण, सहायक आचार्यगण, शोधार्थी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गयीं तथा उनके समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

शारदीय नवरात्र के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा थाना दारागंज अंतर्गत अलोप शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर का भ्रमण कर कानून एवं शान्ति व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त झूंसी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सड़क पर उतरीं महिला पुलिसकर्मी कौशाम्बी में गूँजी महिला शक्ति की आवाज

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। महिला सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में रविवार को मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत महिला पुलिस कर्मियों ने भव्य बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस पहल ने जिले में पुलिस की सकारात्मक छवि को और मज़बूत किया है।

ज्ञात हो कि रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी राजेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर किया। महिला थाना प्रभारी के साथ 15 महिला उप निरीक्षक, 55 महिला आरक्षी और 10 महिला उप आरक्षी इस रैली में शामिल हुईं। बाइक रैली पुलिस कार्यालय से रवाना होकर मंझनपुर चौराहा, राम मंदिर चौराहा, सोनारन टोला, समदा चौराहा होते हुए करीब 5 किलोमीटर का सफर तय कर पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर समाप्त हुई।

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि 'इस रैली का उद्देश्य महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुँचाना है। जब महिलाएं सुरक्षित होंगी, तभी समाज और राष्ट्र प्रगति कर सकेगा।' रैली के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने राहगीरों और आमजन को मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी और शासन-प्रशासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों के महत्व से अवगत कराया। खासतौर पर महिलाओं और बच्चियों को यह नंबर बताए गए -

1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1090 (वीमेन पावर हेल्पलाइन), 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन), 102 (स्वास्थ्य सेवा), 108 (एम्बुलेंस सेवा), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)।

जिलाधिकारी ने आई.जी.आर.एस. शिकायत के निस्तारण की स्थिति का मौके पर जाकर किया सत्यापन

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधूसूदन हुल्गी ने आज तहसील चायल में प्राप्त आई.जी.आर.एस. शिकायत के निस्तारण की स्थिति का मौके पर जाकर उप जिलाधिकारी एवं शिकायतकर्ता की उपस्थिति में सत्यापन किया। आई.जी.आर.एस. संदर्भ संख्या-20017425012475, शिकायतकर्ता उमेश कुमार साहू निवासी-महमूदपुर की शिकायत के सम्बन्ध में तहसील प्रशासन द्वारा मौके पर जाकर जॉच की गई। जॉच 02 पक्षों में स्वामित्व को लेकर विवाद पाया गया। दोनों पक्षों को न्यायालय में वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। निस्तारण आख्या सही पाई गई।

डीएम ने मूर्ति विसर्जन स्थल पक्का तालाब का भ्रमण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कौशाम्बी। जिलाधिकारी ने पक्का तालाब, मूरतगंज का भ्रमण कर मूर्ति विसर्जन स्थल से सम्बन्धित की गई तैयारियों/कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि तालाब की साफ-सफाई करा लिया जाय। इसके साथ ही उन्होंने मूरतगंज के अन्तर्गत पण्डालों का भ्रमण कर पदाधिकारियों से कहा कि सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाय तथा सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाय। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को साफ-सफाई एवं पेयजल सहित आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

नगर पालिका में महिलाओं को जागरूक किया

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। नगर पालिका परिषद भरवारी कार्यालय में सोमवार को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए संचालित मिशन शक्ति-5 अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर क्षेत्र कि महिलाओं व नगर पालिका कार्यालय में तैनात महिला कर्मचारियों को योजना की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। एसएचओ कोखराज चन्द्रभूषण मौर्य, उपनिरीक्षक कोखराज विंध्यवासिनी ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों व टोल फ्री नम्बरों की जानकारियां दी। कार्यक्रम में बोर्ड की महिला सभासदों, महिला ब्रांड अम्बेसडर, महिला पुलिसकर्मी एवं महिला सफाई मित्रों के साथ मिशन शक्ति-5 का शुभारम्भ किया गया।

कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष कविता पासी, अधिशासी अधिकारी राम सिंह, अवर अभियंता बुद्धराज पाल, लेखा लिपिक बबलू गौतम, वार्ड के सभासद व अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे।

आरेडिका में राजभाषा पुरस्कार वितरण एवं विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन

मंत्र भारत संवाददाता

रायबरेली। आरेडिका में राजभाषा विभाग के तत्वावधान तथा मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रमेश चन्द के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक काम करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से राजभाषा पखवाडा के तहत दिनांक-17.09.2025 से 27.09.2025 तक विभिन्न राजभाषा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में आज दिनांक-22.09.2025 को सरस्वती प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक संध्या एवं विशाल कवि सम्मेलन तथा राजभाषा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आरेडिका महाप्रबंधक प्रशान्त कुमार मिश्रा तथा आरेडिका महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा भारती मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एवं आरेडिका की हिंदी त्रैमासिक प्रगति पत्रिका के सितम्बर अंक का विमोचन

किया।

इस सम्मेलन में काव्य/गीत के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर चुके प्रतिष्ठित कवि मुकुल महान (हास्य कवि), अरविन्द झा (हास्य कवि) शिखा श्रीवास्तव (शृंगार कवयित्री), योगेश शुक्ला (गीत) एवं प्रो0 डा0 विनम्र सेन सिंह (गीत समसामायिक) ने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। साथ ही आरेडिका की कनिष्ठ लिपिक प्रियंका राणा ने एकल नृत्य और बच्चों द्वारा समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। कवियों नें अपनी रचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर समां बाँध दिया। शृंगार कवयित्री शिखा श्रीवास्तव ने भी दर्शको से खचाखच भरे प्रेक्षागृह में अपनी रचनाओं पर खूब तालियां बटोरी।

आरेडिका के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित अधिकारियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता में अनिल कुमार श्रीवास्तव जनसम्पर्क अधिकारी ने प्रथम एवं शबीह अहमद वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता द्वितीय तथा मोहित तिवारी उप मुख्य यांत्रिक अभियंता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि कर्मचारी निबंध लेखन प्रतियोगिता में हिमांशु द्विवेदी तकनीशियन, ब्रजेश कुमार वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, तथा राजेश कुमार यादव तकनीशियन ने क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।

वाक् प्रतियोगिता में हिमांशु द्विवेदी तकनीशियन ने प्रथम एवं शिखा रावत मुख्य कार्यालय अधीक्षक ने द्वितीय तथा भावना मुख्य कार्यालय अधीक्षक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाप्रबंधक प्रशान्त कुमार मिश्रा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर आरेडिका के मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रमेश चन्द, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता विवेक खरे, प्रधान वित्त सलाहकार बत्ती लाल मीना, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी अष्टानन्द पाठक, राजभाषा अधिकारी राकेश रंजन तथा आरेडिका महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने किया बैनामा विलेख का स्थलीय सत्यापन

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनपद के विभिन्न उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत होने वाले विक्रय विलेखों में सबसे बडे मूल्य के विक्रय विलेख में से तहसील चायल के उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकृत विक्रय विलेख सख्या- 5100/2025 का स्थलीय सत्यापन किया।

ज्ञात हो कि विक्रय विलेख मौजा महमूदपुर, मनौरी का है, जो मनौरी से सराय अकिल जाने वाली पक्की सड़क/मार्ग से सटी हुई। विक्रीत भूमि सिगमेन्ट के अन्तर्गत आती है। विक्रीत भूमि व्यवसायिक गतिविधियों के 50 मीटर के अन्दर दर्शाया गया था। जिलाधिकारी ने इस विलेख के सम्बन्ध में उप निबन्धक, चायल को स्टाम्प आंगणन कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी चायल आकाश सिंह व उप निबंधक चायल उपस्थित रहें।

मेडिकल कॉलेज में नव प्रवेशी एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं का फाउंडेशन कोर्स शुरू

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में छात्रों को मिला अनुशासन व सहानुभूति का मंत्र

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। शहर के ऐतिहासिक मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सोमवार को एमबीबीएस 2025-26 बैच के नवप्रवेशी छात्रों का फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ। यह कार्यक्रम नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वी.के. पांडेय ने विद्यार्थियों को स्व-देखभाल, अनुशासन, निष्ठा और सहानुभूति का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि समाज सेवा और जिम्मेदारी का भी परिचायक है।

इस अवसर पर बायोकैमिस्ट्री विभागाध्यक्ष प्रो. बीनू, फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. प्रीति गुप्ता, हॉस्टल वार्डन डॉ. बादल सिंह, डॉ. अर्चना कौल, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की प्रो. खुर्शीद परवीन और सांस्कृतिक गतिविधियों की नोडल अधिकारी प्रो. सूबिया करीम अंसारी ने छात्रों को मेडिकल शिक्षा और कॉलेज जीवन की बारीकियों से अवगत कराया। प्रॉक्टर व यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. दिलीप चौरसिया ने एंटी-रैगिंग और शिकायत निवारण नीति पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं लाइब्रेरियन के.पी. सिंह ने केंद्रीय पुस्तकालय की सुविधाओं के बारे में बताया। इस दौरान छात्रों व अभिभावकों ने शिक्षकों, वार्डन और लाइब्रेरियन से संवाद भी किया।

फाउंडेशन कोर्स की संयोजक डॉ. निष्ठा सिंह ने भी नवप्रवेशी छात्रों को मार्गदर्शन दिया और कॉलेज के पहले दिन की गतिविधियों से परिचित कराया।

भदोही में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) 02 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के 01 रिक्त पद हेतु करें आवेदन

इच्छुक व्यक्ति जिलाधिकारी कार्यालय के न्याय सहायक पटल पर अंतिम तिथि 5 अक्टूबर शाम 04 बजे तक संपर्क कर आवेदन प्राप्त व जमा करें

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग -3 (नियुक्तियां) लखनऊ के पत्र के क्रम में जनपद भदोही में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के रिक्त हुए 02 पद एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के रिक्त हुए 01 पद के सापेक्ष विधि परामर्शी के प्रस्तर 7.03 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार कार्य कुशलता एवं वरीयता के आधार पर पैनल गठित कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश प्राप्त है। उक्त के अनुपालन में सहायक जिला शासकीय फौजादारी के रिक्त 02 पद एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व के रिक्त हुए 01 पद के सापेक्ष नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अधिवक्ताओं / विधि व्यवसायियों, जो निम्न प्रतिबन्धों को पूर्ण करते है, वे अपना आवेदन पत्र दो प्रतियो में तीन वर्षों में किए गए ऐसे मुकदमों का विवरण, सम्बन्धित न्यायालय से सत्यापित कराकर, जिसमें वह वादी अथवा प्रतिवादी की ओर से उपस्थित रहें हो, सफलता के प्रतिशत के साथ 05 अक्टूबर 2025 को सायं 04 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के न्याय सहायक पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रतिबन्ध-आवेदक को विधि व्यवसाय का अनुभव सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) पद के लिए 07 वर्ष एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) पद के लिए 10 वर्ष का होना चाहिए। आवेदक की आयु 05 अक्टूबर 2025 तक 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किए गए आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो तो उनके द्वारा दाखिल आयकर विवरणी प्रस्तुत की जायेगी। इच्छुक विधि व्यवसायी जो पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी नैतिक पद पर कार्यरत है अथवा पूर्णकालिक प्रवक्ता हो, उन्हें वर्तमान पद से त्याग पत्र देने के पश्चात् ही पैनल में सम्मिलित किया जायेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजनैतिक क्रियाकलाप में उस समय तक भाग नहीं लेगा जब तक की वह शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य करें अन्यथा वह उक्त पद धारण करने के लिए अनर्ह हो जायेगा। राजनैतिक क्रियाकलाप के अन्तर्गत किसी राजनैतिक दल या स्थानीय निकाय की सदस्यता तथा संवाददाताओं का कार्य भी है। जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को किसी निजी व्यवसाय का अधिकार नहीं होगा। उन्हें केवल राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित निगम, उपक्रम, स्वायत्त शासकीय संस्थाओं, परिषद एवं प्राधिकारियों के वादो की पैरवी शासन के अनुमति से ही करने का अधिकार होगा। आवेदक के विरूद्ध अपराधिक अभियोग पंजीकृत होने अथवा न्यायालय में विचाराधीन होने की दशा में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

इन्हें शासन द्वारा निर्धारित समय-समय पर संशोधित पारिश्रमिक एवं रिटेनर की फीस अनुमन्य होगी और वाद, अपील एवं निगरानी के मूल्यांकन के आधार पर फीस देय नहीं होगी। उन्हें शासकीय कर्मचारियों की कोई सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। इनकी नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप में की जायेगी। समीप के जिलों के अधिवक्ता/विधि व्यवसायी भी जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रिक्त पद के लिए अपने जिलाधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र भेज सकते है, परन्तु इस प्रकार के आवेदन पत्र भी 05 अक्टूबर 2025 को सायं 4 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के न्याय सहायक पटल पर प्राप्त हो जाना चाहिए।

घटी जीएसटी के स्लैब को लेकर फायदे बताएंगे भाजपाई

स्वदेशी सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे भाजपाई

प्रयागराज। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि 22 सितंबर को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर जीएसटी के नए स्लैब में जरूरत की सामग्री पर घटती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ में घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शुरुआत की गई जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि गण बाजार में निकलकर घटी हुई जीएसटी के फायदे बताएंगे और हर घर स्वदेशी घर-घर स्वदेशी अभियान के तहत लोगों को आने वाले पर्वों पर स्वदेशी सामान खरीदने का लोगों को प्रेरित करेंगे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी ,कार्यकर्ता, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के माध्यम से इस अभियान को गति देंगे।

भारत ने दिखाया मार्ग : स्पेन में घोषित हुई सतत जलीय कृषि के लिए क्रांतिकारी बैक्टेरियोफेज़ चिकित्सा

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है, जब भारतीय वैज्ञानिक डॉ. अजय कुमार सोनकर ने समुद्री मोती सीपियों की सर्जरी के बाद उन्हें एंटीबायोटिक-रहित उपचार से ठीक करने की विश्व की पहली तकनीक की घोषणा की। यह क्रांतिकारी खोज आज प्रतिष्ठित यूरोपियन एक्वाकल्चर सोसाइटी, एक्वाकल्चर 2025 सम्मेलन में वैलेंसिया, स्पेन में प्रस्तुत की गई।

डॉ. सोनकर ने अपने शोधपत्र 'मोती सीपों में शल्य चिकित्सा के बाद उपचार के लिए देशी समुद्री जीवाणुभोजी का उपयोगः एंटीबायोटिक दवाओं से एक स्थायी बदलाव' में यह अभिनव तकनीक प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समुद्री बैक्टेरियोफेज़ का उपयोग कर मोती सीपियों को सर्जिकल इम्प्लांटेशन के बाद स्वस्थ करने की प्रक्रिया बताई, जिससे एंटीबायोटिक की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है।

पिछले कई दशकों से, एंटीबायोटिक जलीय कृषि में आवश्यक माने जाते रहे हैं, विशेषकर मोती सीपियों की नाजुक सर्जरी के बाद। लेकिन इनके अत्यधिक प्रयोग से एंटीबायोटिक प्रतिरोध, पारिस्थितिकीय असंतुलन, और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

डॉ. सोनकर की बैक्टेरियोफेज़-आधारित चिकित्सा एक सतत और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जो बैक्टीरिया पर प्राकृतिक नियंत्रण प्रदान करती है और समुद्री पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना मोतियों को सफलतापूर्वक स्वस्थ करती है। नियंत्रित अध्ययनों में इस पद्धति ने सर्जरी के बाद उपचार में असाधारण सफलता दिखाई है, जिससे सीपियों की जीवित रहने की दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। यह नवाचार भविष्य में मछली और अन्य शंख-शैवाल पालन जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो सकता है और एंटीबायोटिक पर वैश्विक निर्भरता घटा सकता है।

डॉ. सोनकर ने कहाः 'यह दुनिया में पहली बार है जब समुद्री सीपियों को सर्जरी के बाद बिना एंटीबायोटिक के ठीक करने की तकनीक सार्वजनिक की जा रही है। यह भारत की स्वदेशी विज्ञान शक्ति को दर्शाता है, जो वैश्विक जलीय कृषि के लिए एक सतत और स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।'

यह खोज जलीय कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और वैश्विक स्थिरता के

लिए भी महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक का उपयोग घटाकर यह एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसी गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का भी प्रत्यक्ष समर्थन करती है, जिनमें सतत खाद्य उत्पादन, जल-जीव संरक्षण और जिम्मेदार नवाचार शामिल हैं।

इस उपलब्धि के साथ भारत ने वैश्विक जलीय कृषि की दिशा बदलने में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। डॉ. सोनकर का कार्य इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार स्थानीय पारिस्थितिकियों में निहित वैज्ञानिक नवाचार पूरी दुनिया के लिए समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। यह न केवल खाद्य सुरक्षा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जन-स्वास्थ्य जैसे साझा वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में भारत के योगदान को भी रेखांकित करता है।

इस पहली सार्वजनिक घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, उद्योग जगत और नीतिनिर्माताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित होना तय है। यह तकनीक केवल मोती सीपियों की सर्जरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करेगी, बैक्टेरियोफेज़-आधारित, एंटीबायोटिक-रहित जलीय कृषि का युग।

डॉ. अजय कुमार सोनकर जलीय कृषि, मोती विज्ञान और समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात वैज्ञानिक हैं। उनका अनुसंधान पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का उदाहरण है, जिसने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त नवाचारों को जन्म दिया है जो स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाते हैं।

23 सितंबर को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध की अवशेषों को लेकर रुस के लिए करेंगे प्रस्थान

भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार कहा प्रयागराज के लिए गौरव का पल

प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पीएमओ इंडिया के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर 23 सितंबर को वायु सेवा के विशेषविमान से रूस के लिए प्रस्थान करेंगे।

भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता एवं महापौर गणेश केसरवानी ने खुशी जताते हुए कहा कि यह प्रयागराज के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री और प्रयागराज के गौरव माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को भगवान बुद्ध जी की अवशेष कला-कृतियों को रूस ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ जो प्रयागराज के लिए गौरव का पल होगा इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री एवं पीएमओ इंडिया के प्रति हृदय से आभार है और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को हृदय से बधाई है।

मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रूस के कालमिकिया गणराज्य में भारत सरकार का सस्कृति मंत्रालय मंत्रालय भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों का प्रदर्शन करेगा इस प्रदर्शनी के माध्यम से हर एक देश में भारतीय आध्यात्मिक धरोहरों के संरक्षण संवर्धन और प्रचार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होगी। प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताने एवं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद को बधाई वालों में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता, कुंज बिहारी मिश्रा ,वरुण केसरवानी डॉक्टर शैलेश पांडे, राजेश केसरवानी, विवेक मिश्रा,पवन श्रीवास्तव,रमेश पासी,विवेक अग्रवाल, पार्षद किरन जायसवाल, प्रमोद मोदी, गिरजेश मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, विजय पटेल, विजय श्रीवास्तव, सुजीत कुशवाहा, अजय सिंह, अजय अग्रहरि, कमलेश कुमार, शत्रुघ्न जायसवाल आदि सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।

नवरात्रि के पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन में स्टेम सेल थैरेपी कैम्प का शुभारम्भ

नवरात्रि के प्रथम दिन उत्तराखंड़ आपदा पीड़ितों के लिये विशेष प्रार्थना व यज्ञ : स्वामी चिदानन्द सरस्वती

मंत्र भारत संवाददाता

ऋषिकेश। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व, माँ दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का अवसर है। नौ दिवसीय इस महोत्सव को परमार्थ निकेतन में सेवा अनुष्ठान के रूप में समर्पित किया। नवरात्रि के अवसर पर मां हमें स्मरण कराती है कि जब-जब संसार में अंधकार, दुर्बलता और दुःख छाते हैं, तब शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा आशा और साहस का संचार करती हैं।

नवरात्रि के पावन अवसर पर, परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी और साध्वी भगवती सरस्वती जी के पावन सान्निध्य में स्टेम सेल थैरेपी कैंप का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। यह कैंप आधुनिक विज्ञान और सनातन संस्कृति की सेवा-परंपरा का संगम है। हमारी ऋषि परंपरा ने सदैव स्वास्थ्य को धर्म का प्रथम आधार माना है। शास्त्रों में कहा गया है शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् अर्थात् धर्म और कर्तव्य पालन के लिए स्वस्थ शरीर ही प्रथम साधन है। यही भाव इस कैंप की नींव में है।

नवरात्रि के इस पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन में उत्तराखंड की आपदा पीड़ितों की आत्मा की शान्ति व पीड़ित परिवारों की सुख समृद्धि हेतु विशेष प्रार्थना की गयी। स्वामी जी ने कहा कि इस बार उत्तराखंड़ में प्राकृतिक आपदा ने जीवन और घर-परिवार को गहरी चोट पहुँचाई है। मां से प्रार्थना हैं कि प्रभावित परिवारों को शक्ति, साहस और संबल प्रदान करे तथा प्रदेश शीघ्र पुनर्निर्माण की राह पर अग्रसर हो।

स्वामी जी ने कहा कि आज नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के दिव्य दर्शन से जीवन में शांति,

संतुलन और निर्मलता का संचार होता है। यह पर्व केवल आराधना ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आंतरिक शुद्धि का भी अवसर है। वर्ष में दो बार आने वाली नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के साथ हमें शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाने की प्रेरणा देती है।

नवरात्रि की नौ रातें हमारे जीवन के तीन गुणों की यात्रा हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। पहले तीन दिन माँ दुर्गा की उपासना तमोगुण का नाश करती है। अगले तीन दिन माँ लक्ष्मी की आराधना रजोगुण को संतुलित करती है। अंतिम तीन दिन माँ सरस्वती की पूजा सतोगुण को जागृत करती है।

यह पर्व अज्ञान से ज्ञान की ओर, असंतुलन से सामंजस्य की ओर और दुर्बलता से शक्ति की ओर बढ़ने की आध्यात्मिक साधना है। आइए इस नवरात्रि शक्ति का पूजन करें, शांति की स्थापना करें, स्वयं को सशक्त करें और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं।

साध्वी भगवती सरस्वती जी ने कहा कि स्टेम सेल थैरेपी कैंप केवल चिकित्सा का केंद्र नहीं, बल्कि नयी आशा का दीपक है। आधुनिक विज्ञान की प्रगति और प्राचीन दर्शन की करुणा जब एक साथ आती है, तो समाज के लिए अमृत बन जाती है। इस कैंप का उद्देश्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को केवल उपचार देना नहीं, बल्कि जीवन में नयी ऊर्जा, नयी प्रेरणा और नयी दृष्टि देना भी है। कैंप के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बीमारी केवल शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की स्थिति से भी जुड़ी है इसलिए यहाँ उपचार केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दिशा में भी किया जाना जरूरी है।

डॉ. सुनीता राणा अग्रवाल, आर. अग्रवाल हॉस्पिटल्स एवं जीन रिसर्च फाउंडेशन, बैंगलोर और उनकी टीम ने इम्यून बूस्टर स्टेम सेल इंजेक्शन लगाकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेजा का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं का लिया जायजा

केन्द्र में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक न पाये जाने पर जतायी नाराजगी, अभियान चलाकर व्यवस्था चुस्त-दूरूस्त बनाने के दिए निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेजा, गौ-आश्रय स्थल कपूरी, निर्माणाधीन आईटीआई पथरपाल-कोरांव, निर्माणाधीन सड़क एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही पानी की टंकियों के निर्माण की प्रगति एवं जलापूर्ति की स्थिति का औचक निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित अधिकारियों को अवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेजा में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिये जाने एवं चिकित्सालय में उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की अद्यतन स्थिति का आंकलन किए जाने हेतु औचक निरीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई की व्यवस्था, चिकित्सकों और स्टॉफ की उपलब्धता एवं उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति, चिकित्सकीय जांच की मशीनों की उपलब्धता एवं संचालन, अभिलेखों की स्थिति, जनसामान्य हेतु उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, महिला प्रसव वार्ड की स्थिति, एम्बुलेंस एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था न होने, शौचालयों नियामित सफाई न होने, चिकित्सालय परिसर में कूड़ा इक्टठा होने एवं कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था अच्छी न होने, कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ-सफाई की नियमित एवं उचित व्यवस्था बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को चिकित्सालय परिसर में अभियान चलाकर साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयें मरीजों से उनका हालचाल जाना और उन्हें चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं है, दवाएं बाहर से तो नहीं मंगायी जा रही है, की जानकारी लिए जाने पर बताया गया कि दवाएं हॉस्पिटल से ही उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण करते हुए दवाओं के स्टॉक, उनकी एक्सपायरी डेट भी देखा एवं किन दवाओं की ज्यादा मांग है और उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी लिए जाने पर सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध पायी गयी। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में आने वाले लोगो के बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक केन्द्र का निरीक्षण करते हुए चिकित्सालय में नियुक्त सभी चिकित्सकों की ड्यूटी का विवरण बोर्ड लगाये जाने एवं पुरूष और महिला वार्ड कक्ष के बाहर वार्ड में भर्ती किए गए लोगो का विवरण चस्पा करने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली, जिसपर उन्हें बताया गया कि चिकित्सालय में पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थिति पंजिका की जांच करते हुए सभी चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ को ड्यूटी के अनुसार समय से चिकित्सालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी मेजा, उपजिलाधिकारी कोरांव, जिला विकास अधिकारी जी0पी0 कुशवाहा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतोष कुमार, खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य सभी सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को जल जीवन मिशन के तहत तहसील मेजा अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौसिया दुबे, ग्राम पंचायत पथरताल एवं कोरांव तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत कपूरी में बनायी जा रही पानी की टंकी एवं वाटर सप्लाई की अद्यतन स्थिति का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया एवं सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। ग्राम पंचायत पौसिया दुबे में पानी की टंकी बनाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पाइप लाइन भी बिछाई जा चुकी है, किंतु अभी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। पानी की सप्लाई की टेस्टिंग का कार्य हो रहा है, जिसपर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को टेस्टिंग के कार्य को जल्द से जल्द कराते हुए टेस्टिंग में लिकेज की आ रही समस्याओं को दूर कराते हुए जल्द से जल्द पानी की सप्लाई शुरू कराये जाने के निर्देश दिए है। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने तहसील मेजा के ग्राम पंचायत पथरताल में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी का निरीक्षण किया। पानी की लाइन बिछाये जाने एवं पानी की टंकी एवं अन्य निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यो को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। तहसील कोराव अन्तर्गत ग्राम पंचायत कपूरी जोन 4 में इससे 05 ग्रामों में जल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण में कार्य प्रगति धीमे पाए जाने पर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए कहा है।

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के टंकियों निरीक्षण के दौरान मौजूद किसानों के साथ बात करते हुए उनसे खाद, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सहित अन्य विषयों के बारे में जानकारी ली। किसानों के द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि यहां पर खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है तथा सिंचाई की कोई समस्या नहीं है। जिलाधिकारी ने उपस्थित किसानों को रासायनिक उर्वरको पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ जैविक कृषि अपनाने हेतु प्रेरित किया।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को कोरांव में प्रांतीय खण्ड-लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही कपुरी बेलहट सड़क का निरीक्षण किया और अवर अभियंता से सड़क एवं निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने कार्य की प्रगति में तेजी लाते हुए निर्धारित समय सीमा मार्च-2026 तक कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने कपूरी गौवंश आश्रय स्थल-कोरांव का निरीक्षण करते हुए गौ संरक्षण केन्द्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का जायजा लेते हुए वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें चुस्त-दूरूस्त बनाये रखने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने गौशाला के प्रवेश द्वार के आकार को बढ़ाकर गेट लगाये जाने एवं गौशाला में एक बोर्ड लगाये जाने का निर्देश दिया, जिसमें सम्बंधित निराश्रित गौआश्रय स्थल का नाम, नियुक्त गौपालकों का नाम व अन्य विवरण उल्लिखित हो। उन्होंने निराश्रित गौवंशों की अधिक संख्या होने के दृष्टिगत एक अतिरिक्त शेड बनाये जाने तथा गौवंशों के लिए बनाये गये शेड के बाहर की तरफ स्थायी टेंट लगाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने गौशाला में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने, परिसर को साफ-सुथरा बनाये रखने, गौवंशों के बच्चों के लिए एक छोटी शेड और वहां पर कम ऊचाई के खाने की नांद बनाये जाने के लिए कहा है। उन्होंने चारे के स्टॉक एवं हरे चारे की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए हरे चारे की बुआई कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि हरे चारे, भूसा इत्यादि की कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि गौशाला में कहीं पर जल-भराव एवं कीचड़ की स्थिति न हो, इसके लिए नियमित साफ-सफाई होती रहे। जिलाधिकारी ने गौशाला के सुंदरीकरण एवं गौशाला परिसर में जल्दी ग्रोथ वाले छायादार पौधे लगाये जाने के लिए निर्देशित किया है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को तहसील कोरांव अन्तर्गत निर्माणाधीन आईटीआई पथरपाल-कोरांव का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।

निरीक्षण के दौरान आईटीआई का निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य का 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी के द्वारा कार्य की गुणवत्ता की जांच करते हुए अवशेष कार्यों के निर्माण की प्रगति एवं कब तक कार्य पूरा होगा, के बारे में जानकारी लिए जाने पर पता चला कि अवशेष कार्यों के लिए विगत छः माह से टेण्डर की कार्यवाही ही नहीं हुई है, जिसपर उन्होंने परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं अवशेष कार्यों हेतु शीघ्र टेण्डर की कार्यवाही पूरी करते हुए अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है।

प्राथमिक विद्यालय मटियारा में नवरात्रि पूजा

थरवई। विकासखंड सोराम के प्राथमिक विद्यालय मटियारा में सोमवार को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत श्रद्धा और उल्लास के साथ हुई। प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना विधि-विधान से संपन्न की गई।इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को नवरात्रि के महत्व और भारतीय संस्कृति की परंपराओं से जुड़ने का संदेश दिया गया। पूजा-अर्चना के उपरांत विद्यालय परिवार की ओर से महाप्रसाद का वितरण किया गया।कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका डॉ. रीना सिंह, मधुलिका सिंह, अखिलेंद्र, प्रियंका, शैल मिश्रा, सुप्रिया, अर्चना, आरती पटेल और वंदना मिश्रा सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।

आरएएफ 91 बटालियन में मां भगवती की पूजा-अर्चना

थरवई। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र स्थित आरएएफ 91 बटालियन डी कंपनी में सोमवार को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां भगवती की पूजा-अर्चना आचार्य पुरोहित अमित पाठक द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना एवं देवी की आराधना सम्पन्न कराई गई।इस अवसर पर उप कमांडेंट प्रमोद कुमार, सहायक कमांडेंट विवेक कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट महेंद्र कुमार, निरीक्षक अमित कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारीजवान कार्यक्रम मेंउपस्थित रहे। पूजा-अर्चना के दौरान पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और सभी ने मां भगवती से सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना

थरवई। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर श्रद्धा और उत्साह के साथ मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना एवं कलश स्थापना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी ग्रुप केंद्र धीरज कुमार ने विधि-विधान से वैदिक मंत्रऊच्चारण के बीचकलश स्थापना की गई इसके उपरांत मां दुर्गा की आराधना एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया।इस अवसर पर अधिकारियों एवं कार्मिकों ने सामूहिक रूप से मां दुर्गा से सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। आयोजन में प्रमुख रूप से कमांडेंट उदय प्रताप सिंह, कमांडेंट डॉ. बी.सी. यादव, उप कमांडेंट श्रीनिवास, उप कमांडेंट राकेश त्रिपाठी, उप कमांडेंट मंत्रालय के.के. झा, सहायक कमांडेंट अविनाश राय, सहायक कमांडेंट प्रभात पांडेय, शैलेश कुमार सिंह, महाराणा वीरेंद्र प्रताप सिंह, समय जैन सहित अन्य अधीनस्थ अधिकारीगण, जवान, महिला कार्मिक एवं परिवारजन मौजूद रहे।

श्रद्धा श्रीवास्तव प्राथमिक शिक्षक संघ की राष्ट्रीय काउंसलर बनी

प्रयागराज।उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश संगठन मंत्री श्रद्धा श्रीवास्तव को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का राष्ट्रीय काउंसलर नामित किया गया है। श्रद्धा श्रीवास्तव वर्तमान में विकासखंड सैदाबाद के प्राथमिक विद्यालय सिठौली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनके काउंसलर नियुक्त होने पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ प्रयागराज के शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है।जिला अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी जिला महामंत्री प्रशांत ओझा जिला उपाध्यक्ष देवव्रत द्विवेदी सहित जनपद प्रयागराज के विभिन्न ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी ने उनके चयन पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा इससे जनपद प्रयागराज के शिक्षकों की बात ज्यादा मजबूती से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकेगी।

सम्पादकीय

रूस की चेतावनी नई वैश्विक कूटनीतिक व्यवस्था का संकेत

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि भारत और चीन पर अमेरिका की टैरिफ धमकी बेअसर हो रही है और वाशिंगटन में दोनों प्राचीन सभ्यताओं के साथ ऐसी भाषा के प्रयोग की निरर्थकता को लेकर बहस चल पड़ी है।

भारत और चीन के खिलाफ जारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ युद्ध के खिलाफ रूस का खुलकर उतरना वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का उदाहरण है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दोनों देशों के पक्ष में खुलकर उतरना यह साबित करता है कि तीनों ही देश कम से कम आर्थिक विषयों के मामले में साथ आ रहे हैं। रूस का खुलकर भारत और चीन का साथ देना और अमेरिका का विरोध करना, वैश्विक दादागिरी वाली अमेरिकी कूटनीति को सीधी चुनौती कही जा सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन 17 सितंबर के दिन बधाई देकर एक तरह से दोनों देशों के रिश्तों में टैरिफ युद्ध के चलते आई तल्खी को कम करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन जमीनी स्तर पर अमेरिकी रूख में कोई बदलाव नहीं आने की वजह से वास्तविक हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे मौके पर सर्गेई लावरोव का बयान एक तरह से अमेरिका को चेतावनी हो सकता है।

भारत से अमेरिका को होने वाले आयात पर पचास प्रतिशत का टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका ने रूस से भारत द्वारा कच्चा तेल खरीदने को कारण बताया है। अमेरिका का कहना है कि भारत ऐसा करके रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग कर रहा है। हालांकि भारत इससे इनकार करता रहा है। भारत वैसे भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों में निचले पायदान पर है। हां, भारत की रूस से नजदीकी रही है और वह बनी हुई है। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में रूस से भारत की नजदीकी दशकों से बनी हुई है। अमेरिका इससे चिढ़ता रहा है। हालांकि पिछले करीब दो दशकों से इसमें कमी आई है। इसकी वजह भारत का विशाल मध्य वर्गीय बाजार रहा है। जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन ट्रंप काल में आए टैरिफ बम के चलते इसमें गिरावट आ रही है।

सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को एक तरह से चेतावनी दी, अपने ही देश के मुख्य टीवी चैनल 1टीवी के कार्यक्रम 'द ग्रेट गेम' में उन्होंने कहा कि चीन और भारत प्राचीन सभ्यताएं हैं। उनसे इस तरह से बात करना कि या तो आप वह बंद कर दें जो हम नहीं चाहते या हम आप पर टैरिफ थोप देंगे, काम नहीं कर पाया।

सर्गेई ने इस कार्यक्रम में एक तरह चुटकी भी ली। उन्होंने अमेरिका के चीन और भारत से जारी रिश्तों को लेकर कहा कि चीन और भारत से जिस तरह का अमेरिकी संपर्क जारी है, वह दिखाता है कि अमेरिकी पक्ष वैश्विक कूटनीति में आ रहे बदलावों को समझ चुका है।

लावरोव ने अमेरिका के प्रति भारत और चीन की प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि अमेरिकी कदम से दोनों देशों को थोड़ी आर्थिक परेशानी जरूर हुई, क्योंकि दोनों ही देशों यानी चीन और भारत को नए बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोतों की तलाश करने और ज्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस अमेरिकी रवैये का नैतिक और राजनीतिक विरोध भी हो रहा है।

लावरोव का यह कहना भी कि रूस पर नए प्रतिबंधों से कोई खतरा नहीं है, बहुत मानीखेज है। इसका मतलब यह है कि रूस कम से कम इस वक्त अमेरिकी दबवा में नहीं आने जा रहा। रूस पर वैसे ही बाइडन प्रशासन के जमाने से कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं, फिर भी रूस की सेहत और कूटनीति पर विशेष असर नहीं पड़ा है। ध्यान देने की बात यह है कि रूस, चीन और भारत की कुल जनसंख्या करीब तीन अरब है। जो वैश्विक जनसंख्या का करीब चालीस फीसद है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीनों देशों की अर्थव्यवस्था की सामूहिक भागीदारी करीब 32 प्रतिशत है। जाहिर है कि दुनिया में इनकी हिस्सेदारी अहम है। ऐसे में लावरोव का बयान एक तरह से अमेरिका को चुनौती ही है कि टैरिफ युद्ध खत्म हो या न हो, तीनों देश कम से कम अपनी आर्थिक चुनौतियों के सामने झुकने नहीं जा रहे।

चुनौती नहीं अवसर है ट्रंप की वीजा नीति, 'इंडियन ब्रेन' अब भारतीय कंपनियों में ऊर्जा लगाएँ और देश को आगे बढ़ाएँ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीज़ा को लेकर जो नया कदम उठाया है, वह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि वैश्विक प्रतिभा प्रवाह (उर्दैत ऊँतहू इत्दै) की दिशा बदलने वाला निर्णय सिद्ध हो सकता है। इस नीति के अंतर्गत हर वर्ष एच-1बी वीज़ा के लिए कंपनियों को एक लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) शुल्क देना होगा। यह राशि वर्तमान ढांचे की तुलना में कई गुना अधिक है और सीधे-सीधे उन कंपनियों पर बोझ डालेगी जो भारतीय और चीनी पेशेवरों पर निर्भर हैं।

दरअसल, ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। उनके अनुसार, जब अमेरिकी विश्वविद्यालय हर साल लाखों ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं तो कंपनियों को चाहिए कि वे उन्हीं को प्रशिक्षित करें और काम दें। यह कदम उनके 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ ही, 'प्रोजेक्ट फ़ायरवॉल' नामक नई पहल भी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनियों द्वारा वीज़ा दुरुपयोग पर रोक लगाना है। ट्रंप का कहना है कि अब तक एच-1बी वीज़ा का इस्तेमाल कंपनियां वेतन दबाने और अमेरिकी युवाओं की नौकरियां छीनने के लिए करती रही हैं। नई व्यवस्था में कंपनियों को भारी-भरकम शुल्क चुकाना होगा, जिससे वे विवश होकर स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देंगी।

हम आपको बता दें कि अमेरिका की अधिकांश टेक कंपनियां– जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा और

जेपी मॉर्गन जैसी दिग्गज शामिल हैं, वह भारतीय प्रतिभाओं पर काफी हद तक निर्भर हैं। केवल 2025 की पहली छमाही में ही अमेज़न और उसकी क्लाउड इकाई ने 12, 000 से अधिक एच-1बी वीज़ा मंज़ूर करवाए। देखा जाये तो भारत अकेले लगभग 71इ एच-1बी वीज़ा का लाभार्थी है। टेक कंपनियों का तर्क है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय इतनी मात्रा में कुशल इंजीनियर और प्रोग्रामर तैयार नहीं कर पा रहे जो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें। इस स्थिति में भारतीय और अन्य एशियाई देशों के पेशेवर ही उनकी रीढ़ बने हुए हैं। अब ट्रंप के नये फैसले के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क बढ़ाने से अमेरिका अपनी नवाचार क्षमता खो सकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी की होड़ में चीन से पिछड़ सकता है।

ट्रंप के फैसले का भारत पर क्या असर होगा यदि इसकी चर्चा करें तो आपको बता दें कि भारत इस नीति से सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि हर साल हज़ारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और वित्त विशेषज्ञ एच-1बी वीज़ा के जरिए अमेरिका जाते हैं। देखा जाये तो भारतीय युवाओं के लिए अमेरिकी नौकरी बाज़ार का दरवाज़ा सीमित हो जाएगा। इससे उनके सपनों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनियां अमेरिकी प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका भेजती रही हैं। नई नीति से इनकी लागत बढ़ेगी और प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है। साथ ही ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर यह हो सकता है कि अब तक जो उच्च कुशल प्रतिभा अमेरिका चली जाती थी, वह भारत में ही रहकर यहां की कंपनियों के लिए काम करेगी।

देखा जाये तो ट्रंप के फैसले को केवल नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के लिए यह एक अवसर भी है। अब तक देखा गया है कि भारतीय मूल के कई दिग्गज अमेरिकी कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं। जैसे सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, अजय बंगा आदि। यदि यही प्रतिभा भारत में रहकर देश की कंपनियों को आगे बढ़ाती तो भारत की वैश्विक स्थिति कहीं और होती। देखा जाये तो जब वैश्विक दरवाज़े सीमित होंगे तो भारत में स्टार्टअप कल्चर और मज़बूत हो सकता है। भारत सरकार के पास यह मौका है कि वह उच्च कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए टैक्स लाभ, बेहतर रिसर्च सुविधाएँ और आसान कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराए।

यदि भारत सरकार मजबूत ढांचा विकसित करे तो भारतीय युवाओं को अमेरिका जाने की आवश्यकता कम होगी। इसके अलावा, अमेरिका में काम करने वाली भारतीय प्रतिभा यदि भारत लौटती है तो सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिससे ये लोग यहां की कंपनियों को आगे बढ़ाएं। साथ ही, उच्च कौशल वाले पेशेवरों को टैक्स में छूट, आसान फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप का यह निर्णय अमेरिका के लिए शायद तत्कालिक राजनीतिक लाभ ला सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह कदम उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर, भारत को इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। अब तक कुशल भारतीय पेशेवरों का मस्तिष्क और मेहनत अमेरिकी कंपनियों के लिए संपत्ति बनता रहा है। यदि यही प्रतिभा भारत में रहकर भारतीय कंपनियों के लिए काम करे तो न केवल भारतीय उद्योग जगत बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति तेज़ हो सकती है।

आज भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों के शीर्ष पदों पर भारतीय बैठे हैं। अगर यही 'इंडियन ब्रेन' भारत की कंपनियों में अपनी ऊर्जा लगाएँ, तो इसका लाभ सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को मिलेगा। भारत सरकार को चाहिए कि इसे अवसर मानकर उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए सुविधाजनक माहौल और प्रोत्साहन तैयार करे। बहरहाल, ट्रंप की यह नीति भारत के लिए मस्तिष्क पलायन को रोकने और प्रतिभा को देश में ही बनाए रखने का सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।

यूएन में किससे भिड़ गए ट्रंप, चीन भी देखता रह गया जीत गया बलूचिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में क्या-क्या हुआ?

पाकिस्तान और चीन को अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल, पाकिस्तान और उसका करीबी चीन बलूच लिबरेशन आर्मी और उसकी मजीद ब्रिगेड को संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी सूची में डालना चाहते थे। लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। पाकिस्तान और चीन चाहता था कि बीएलए को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया जाए। लेकिन अमेरिका समेत फ्रांस और ब्रिटेन ने इससे हाथ खींच लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267वीं प्रतिबंध समिती के तहत पाकिस्तान और चीन ने एक प्रस्ताव रखा था। इसमें मांग की गई थी कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसका आत्मघाती दस्ता मजीद ब्रिगेड को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया जाए।

लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। अमेरिका के साथ फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान और चीन का साथ देने से इनकार कर दिया। जिसकी वजह से ये प्रस्ताव गिर गया। अमेरिका ने साफ कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी का अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से कोई संबंध नहीं है। हालांकि अमेरिका खुद बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन मानता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में 1267 सूची सिर्फ उन्हीं संगठनों के लिए है जिनका सीधा संबंध अलकायदा या आईएसआईएस से है। बता दें पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तार अहमद ने दावा किया था कि अफगानिस्तान में अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, तहरीक-ए-तालिबान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और बलूच लिबरेशन आर्मी के कम से कम 60 ठिकाने हैं। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1999 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव 1267 पारित किया, जिसके तहत ओसामा बिन लादेन और उसके साथियों को आतंकवादी घोषित किया गया और अल-कायदा, बिन लादेन या तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। यह अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हुआ। प्रस्ताव में आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने, आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और ओसामा बिन लादेन को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। प्रतिबंध लगाने से एक साल से भी कम समय पहले, बिन लादेन ने केन्या के नैरोबी और तंजानिया के दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की थी, जिसमें 224 लोग मारे गए थे और 4, 000 से ज़्यादा घायल हुए थे। प्रस्ताव 1267 ने प्रतिबंध सूची में व्यक्तियों या संस्थाओं को नामित करने और प्रतिबंध उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए एक यूएनएससी समिति की स्थापना की, जिसमें संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध शामिल थे। प्रारंभ में अल-कायदा और तालिबान से संबंधित होने के बावजूद, समिति के अधिदेश को 2015 में संकल्प 2253 के माध्यम से इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट (आईएसआईएल) को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था।

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह देश के लगभग 44इ भूभाग पर फैला है। हालाँकि इसकी अवस्थिति और प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल, की प्रचुरता इसे पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी कम है और देश के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ के लोग गरीब हैं। 1948 में जब पूर्ववर्ती बलूच सरदारों को पाकिस्तान में विलय के लिए मजबूर किया गया था, तब से इस प्रांत ने खूनी विद्रोहों, क्रूर सरकारी दमन और एक स्थायी बलूच राष्ट्रवादी

आंदोलन की एक श्रृंखला देखी है। अब तक, बलूचिस्तान में पाँच 'स्वतंत्रता संग्राम' हो चुके हैं, जो 1948, 1958-59, 1962-63, 1973-77 और 2005-06 के बाद लड़े गए।

पाकिस्तानी सरकार ने इन विद्रोहों से क्रूरता से निपटा है, और उसके सैनिकों पर अपहरण, यातना, मनमानी गिरफ़्तारी और फांसी की कई रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। हालाँकि हताहतों की सही संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन रूढ़िवादी अनुमान भी यही कहते हैं कि सरकारी दमन में हज़ारों लोग मारे गए हैं। गैर-सरकारी संगठन वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के अनुसार, सिर्फ़ 2001 से 2017 के बीच लगभग 5, 228 बलूच लोग लापता हुए हैं।

बीएलए पाकिस्तान का एक उग्रवादी संगठन है, जिसका मकसद पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करती है। पाकिस्तान ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान पर इस संगठन को सपोर्ट करने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि भारत और अफगानिस्तान इस आरोप का विरोध करते रहे हैं। हालांकि बलूच लोग पाक के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन करते हैं।

मजीद ब्रिगेड बलूच लिबरेशन आर्मी के एक स्पेशल विंग है। इस विंग को खास तौर पर आत्मघाती हमलों के लिए भी तैयार किया गया है। इसमें शामिल होने वालों को कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मजीद ब्रिगेड का उद्देश्य खुद को समाप्त कर दुश्मन को खास संदेश देना है। इसमें आम तौर पर युवाओं की भर्ती होती है। इसकी स्थापना साल 2011 में हुई थी। इसका नाम बलूचिस्तान के दो सगे भाइयों लांगो और मजीद के नाम पर रखा गया। इसका नाम पूर्व प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के एक गार्ड के नाम पर रखा गया था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के संस्थापक की हत्या के प्रयास में मारा गया था। न्हें सम्मान देने के लिए ब्रिगेड का नाम मजीद ब्रिगेड रखा गया।

न्याय की रीढ़ पर वार : क्यों जरूरी है अधिवक्ता संरक्षण कानून

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की माँग उत्तर प्रदेश में लगातार तेज़ हो रही है। हापुड़ से वाराणसी तक हुई घटनाओं ने वकीलों की असुरक्षा को उजागर किया है। विधि आयोग और बार काउंसिल अपनी सिफ़ारिशें सरकार को दे चुके हैं। अब ज़रूरत है कि विधानमंडल तुरंत अधिनियम लागू कर न्यायपालिका की रीढ़ को मज़बूती दे।

लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में वकील समाज का अभिन्न हिस्सा है। अदालत की चौखट पर जब आम नागरिक न्याय की उम्मीद लेकर पहुँचता है, तो उसका सबसे बड़ा सहारा अधिवक्ता ही होता है। अधिवक्ता न केवल अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हैं, बल्कि न्यायपालिका और जनसाधारण के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करते हैं। किंतु दुखद है कि जो वर्ग कानून और व्यवस्था की रक्षा करता है, वही आज खुद असुरक्षित है।

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत जुलाई 2021 में हुई, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका मसौदा प्रस्तुत किया। इसमें अधिवक्ताओं को हिंसा, धमकी और उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा के ठोस प्रावधान रखे गए। 2022 में संसद की स्थायी समिति ने मसौदे की समीक्षा कर संशोधनों की सिफारिश की। इसके बाद मार्च 2023 में राजस्थान पहला राज्य बना जिसने यह अधिनियम पारित कर अधिवक्ताओं को सुरक्षा का कवच दिया और अन्य राज्यों में भी उम्मीद जगाई।

उत्तर प्रदेश में यह माँग 29 अगस्त 2023 की हापुड़ घटना के बाद और तीव्र हो गई। उस दिन पुलिस ने न्यायालय परिसर में निहत्थे अधिवक्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। न्याय की रक्षा करने वाले स्वयं न्यायालय परिसर में ही अपमानित और घायल किए गए। यह दृश्य पूरे प्रदेश की बार एसोसिएशनों को झकझोर गया और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की माँग को और प्रबल बना दिया। इसके विरोध में 4 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने तीन-दिवसीय हड़ताल की घोषणा की और अदालतों में कामकाज ठप हो गया।

हापुड़ घटना के बाद 5 सितंबर 2023 को योगी सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का दायित्व था कि वह अधिवक्ताओं से सुझाव लेकर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करे और सरकार को अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने के संबंध में ठोस दिशा-निर्देश दे। 9 सितंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए एक न्यायिक समिति गठित की। समिति को 16 सितंबर से बैठकें शुरू करने का निर्देश दिया गया। अधिवक्ताओं ने पुलिस की बढ़ती दखलअंदाजी, मनमानी गिरफ्तारी और सुरक्षा की कमी की शिकायतें कीं। सितंबर के अंत तक 40 से अधिक शिकायतें मिलीं। अक्टूबर 2023 में अंतरिम रिपोर्ट में अधिवक्ताओं पर हमले को न्यायिक कार्यवाही में गंभीर बाधा बताया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार कर राज्य विधि आयोग को सौंपा। विधि आयोग ने नवंबर 2023 में अपनी सिफारिशें दीं, जिनमें अदालत परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, अधिवक्ताओं को सुरक्षित और पक्के चैंबर उपलब्ध कराने, सामूहिक बीमा योजना लागू करने और महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में उन्हें न्यूनतम पंद्रह हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने का सुझाव शामिल था। आयोग ने यह भी कहा कि किसी अधिवक्ता की गिरफ्तारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न हो और गिरफ्तारी की स्थिति में 24 घंटे के भीतर संबंधित बार एसोसिएशन को सूचना दी जाए। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रारूप में अधिवक्ताओं पर हिंसा, धमकी, उत्पीड़न, संपत्ति का नुकसान और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर छह महीने से पाँच वर्ष तक की सजा और पचास हजार से दस लाख रुपये तक का जुर्माना होगा, जबकि पुनरावृत्ति की स्थिति में यह सजा दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। अदालत को पीड़ित अधिवक्ता को मुआवजा देने का अधिकार होगा।

लेकिन अधिवक्ता समाज को अपेक्षित परिणाम अब तक नहीं मिले। प्रयागराज में अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला की दिनदहाड़े हत्या ने यह संदेश दिया कि पेशेवर दायित्व निभाने वाले वकील भी असुरक्षित हैं। 17 सितंबर 2025 को वाराणसी जिला न्यायालय परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हुआ, जिसमें उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 70 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार किया और अदालतों का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। 19 सितंबर 2025 को चंदौली में अधिवक्ता कमला यादव की हत्या उनके ही भाई द्वारा कर दी गई और मुरादाबाद में एक महिला अधिवक्ता पर रासायनिक हमला हुआ। यह घटनाएँ इस तथ्य को पुष्ट करती हैं कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इन घटनाओं ने अधिवक्ता बिरादरी के आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुँचाया। 'हम अपने परिवार और बच्चों को हर रोज़ यह आश्वासन नहीं दे पा रहे कि हम सुरक्षित लौटेंगे। यह स्थिति अधिवक्ता बिरादरी के आत्मविश्वास को तोड़ रही है।' –वाराणसी के एक वरिष्ठ अधिवक्ता (स्थानीय अखबार से बातचीत, 2024)। युवा वकील और कानून पढ़ रहे छात्र-छात्राएँ अब सवाल करने लगे हैं कि क्या न्याय के लिए लड़ना उनके जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। जब अधिवक्ता भयभीत रहेंगे, तो कौन नागरिक का पक्ष निर्भीक होकर अदालत में रख पाएगा? 'अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल पेशेवर संरक्षण नहीं, बल्कि पूरे समाज के न्याय की सुरक्षा है।' –बार काउंसिल ऑफ यूपी, 2024।

17 सितंबर की वाराणसी घटना के बाद 20 सितंबर 2025 को विधान परिषद सदस्य अशुतोष सिन्हा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने की माँग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी ठोस कदम नहीं उठाती तो अधिवक्ता समाज का धैर्य टूट जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष परेश मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वाराणसी में पुलिस की कथित बर्बरता की मजिस्ट्रेटी जांच और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के त्वरित क्रियान्वयन की माँग की। आज स्थिति यह है कि बार काउंसिल और विधि आयोग दोनों अपनी रिपोर्ट और सुझाव सरकार को दे चुके हैं, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कर उदाहरण प्रस्तुत कर चुका है, किंतु उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं को अब भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली है। 'यदि अधिवक्ता सुरक्षित नहीं होंगे, तो न्यायपालिका की रीढ़ टूट जाएगी। यह केवल वकीलों का प्रश्न नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है।' –उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़।

यहाँ मुद्दा केवल वकीलों की अभिरक्षा और सम्मानजनक वातावरण का नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की आत्मा का है। अधिवक्ता वह दीपक हैं जो अंधेरे में न्याय की लौ जलाए रखते हैं और समाज को अन्याय के अंधकार से मार्गदर्शन देते हैं। यदि यह दीपक डगमगा जाए, तो न केवल अधिवक्ताओं का अस्तित्व संकट में पड़ेगा, बल्कि नागरिकों के न्याय पाने का अधिकार भी कमजोर पड़ जाएगा।

हापुड़ की लाठियाँ, प्रयागराज का खून, वाराणसी का टकराव और मुरादाबाद का अमानवीय हमला हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि अब देर की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अधिनियम वकीलों के जीवन की ढाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सांस है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद को इस पर अब और मौन नहीं रहना चाहिए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर न्याय की ज्योति को बचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। यही समय है, यही अवसर है–यदि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु एवं जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक संपन्न

सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में सभी बैंकों की सभी शाखाएं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरित कराना सुनिश्चित कराये - जिलाधिकारी

उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मण्डल के व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापार से जुड़े अन्य मुद्दो, सुविधाओं एवं समस्याओं पर किया गया चर्चा

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की संयुक्त अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु एवं जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति एवं उद्योग व्यापार मण्डल के व्यापारियों के साथ बैठक आहुत की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि नवरात्रि, रामलीला, भरत मिलाप मेला आदि त्यौहारों के दृष्टिगत अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से कराए। लटके एवं जर्जर तारों को तत्काल बदलवाये। स्वयं फील्ड में निकले और समस्याओं का निराकरण कराए। साथ ही अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देश दिया कि खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत कराए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित उद्यमियों, व्यापारियों से कहा गया कि जिले में व्यापारियों, उद्यमियों निवेशको से संबंधित मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से निर्धारित समयावधि में किया जायेगा। व्यापारियों/उद्यमियों के प्रति सहयोगात्मक रूख अपनाया जाये और उद्यमियों के लम्बित प्रकरणों का नियमानुसार प्राथमिकता पर निस्तारण समय से किया जाये, जिससे कि जनपद में अधिक से अधिक रोजगार के साधन सृजित हों, उद्यमी अपने उद्योग को बेहतर ढंग से संचालित कर सके। साथ ही खाद्यय विभाग, विद्युत विभाग, प्रदूषण विभाग, व्यापारकर विभाग एवं अन्य विभाग के उपस्थित अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित कराये। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नही होगी।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनान्तर्गत विकास खण्डों में लम्बित आवेदन सूरियावा में 30 व ज्ञानपुर में 31 कुल 61 आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि जॉच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रेषित सम्बन्धित विभाग को सुनिश्चित कराये। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान प्रगति समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देश दिया कि जिन बैंको की प्रगति खराब है, उन बैंको के नोडल अधिकारी अगली बैठक में ससमय उपस्थित रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन बैंको की प्रगति खराब है उनकी प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर रिर्पोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने लीड बैंक सहित सभी बैंको के अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष सीएम युवा अभियान को अधिक से अधिक स्वीकृत करें। बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जनपद भदोही में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु लैंड बैंक डाटा उपलब्ध कराने, प्लेज पार्क विकसित करने, सिटी आफ एक्सपोर्ट एक्सलेन्सी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के क्रियान्वयन पर बल दिया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने जनपद के औद्योगिक विकास के क्रम में निवेशकों से मास्टर प्लान पर ही चर्चा किया। उन्होंने बीडा क्षेत्रवासियों से नक्सा पास कराकर ही निर्माण कार्य करने की अपील किया। जिलाधिकारी ने उपयुक्त सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। व्यापारियों, उद्यमियों, निवेशको द्वारा जमीन व राजस्व से जुड़ी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने मीटिंग में जूम मीटिंग से जुडे हुए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में उद्योग अधिकारी आशुतोष सहाय पाठक, निर्यातक पियूष बरनवाल, नीरज जायसवाल, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, नगर पंचायत ज्ञानपुर घनश्यामदास गुप्ता, राकेश वर्मा, अवधेश उमर, रवि जायसवाल, शेषधर गुप्ता, जनपद के व्यापारी, उद्यमी, निवेशक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी गण सहित अन्य सभी सम्बन्धित उपस्थित रहें।

वृन्दावन के कलाकारों द्वारा किया रामलीला का मंचन

मंत्र भारत संवाददाता

सुरियावाँ। श्रीरामलीला समिति द्वारा आयोजित श्रीराम चरित्र प्रदर्शन उत्सव के अंतर्गत सोमवार को धार्मिक रंग में माहौल रंगा हुआ देखने को मिला। वृन्दावन से आये हुवें कलाकारों ने मंच पर नारद मोह, रावण जन्म और वेदवती-रावण संवाद जैसे प्रसंगों का सजीव व भावपूर्ण मंचन कर श्रद्धालुओं और दर्शकों को भावविभोर कर दिया।

नारद मोह प्रसंग में नारद मुनि के अहंकार और भगवान विष्णु की लीला का मनोहारी चित्रण किया गया। वहीं रावण जन्म प्रसंग में उसके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा को प्रभावशाली संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वेदवती और रावण के संवाद ने मंच पर नारी सम्मान और अधर्म के विरुद्ध सत्य की स्थापना का सशक्त संदेश दिया। रावण जन्म प्रसंग में राक्षसी वंश, तपस्या, और रावण के बल-घमंड की शुरुआत को पौराणिक संदर्भों के साथ प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। वृन्दावन के कलाकारों ने समर्पण व निष्ठा के साथ अभिनय कर पौराणिक दृश्यों को जीवंत बना दिया।

इस मौके पर राधेश्याम गुप्ता कलाकार, अवधेश उमर, अशोक, नन्द लाल गुप्ता, अश्वनी साहू, लोकेश सेठ, हरिमोहन, धनश्यामदास, दिलीप मोदनवाल, जितेंद्र कुमार, वैभव, विशाल, राहुल आदि लोग उपस्थित रहें!

पोषण भी-पढ़ाई भी' एवं राष्ट्रीय पोषण माह कार्यशाला संपन्न

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। भारत सरकार के निर्देश के क्रम में एवं जिलाधिकारी शैलेष कुमार के कुशल मार्गदर्शन में 03 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा विकास खण्ड सुरियाँवां में प्रारम्भ हुआ जो 24 सितंबर 2025 तक चलेगा। प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी कार्यकृतियों को प्रथम दिवस पढ़ाई, द्वितीय दिवस पोषण व तृतीय दिवस 'पोषण भी - पढ़ाई भी' पर केन्दित है जिसमें भारत सरकार हारा निर्धारित कैरीकुलम के आधार पर विषयबार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यकम में दिनांक 17 सितंबर से आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह के प्रथम सप्ताह 'मोटापा निवारण-चीनी, नमक एवं तेल के उपभोग में कमी लाने हेतु जागरुकता कार्यक्रम ग्राम स्तर, ब्लाक, जनपद स्तर पर कराये जा रहे कार्यक्रमों के प्रति जागरुक किया गया। 22 सितम्बर से मिशन शक्ति 5 कार्यक्रम में विभिन्न टोल फ्री नंबर 102, 108, 1076, 101, कन्या सुमगला योजना, प्रधानमन्त्री मातृ वंदन योजना, मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 आदि के विषय में व्यापक जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषयों की जानकारी देते हुए जिला कार्यकम अधिकारी दिनेश कुमार मिश्र द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण कार्यक्रम

जिलाधिकारी के नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में निर्धारित मानक के अनुसार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य बाल विकास सेवाओं को जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा जागरुकता से जुड़ा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को शासकीय योजनाओं से परिचित कराना तथा लाभ लेने हेतु प्रेरित करन है ।

कार्यकम में बाल विकास परियोजना अधिकारी सुरियावा अरविंद कुमार जो विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण के कोर्स डारेक्टर है के साथ सीडीपीओ

भदोही सैलाश राम, अभोली श्रीमती शाहिना, मुख्य सेविका श्रीमती शेषकला एवं आंगनवाड़ी कार्यकतियों एवं जन सामान्य ने प्रतिभाग किया।

नगर निकाय कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सख्त, लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

नगर निकाय कार्यों की प्रगति पर जिलाधिकारी की सख्ती, प्लास्टिक पर प्रतिबंध अभियान तेज करने का निर्देश
नगर पालिकाओं में अधूरे कार्यों की जांच, मानक व समयबद्धता से कार्य पूर्ण करने पर जोर

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। नगर निकायों की कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टेड्रट सभागार में सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपीगंज की अनुपस्थिति व बजट का व्यय न करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस के साथ वेतन रोकने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। साथ ही नगर पालिका के कार्यों की जांच करने हेतु भी निर्देश दिया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही को निर्देश दिया कि महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि 15वा वित्त टाइड अन टाइड फंड एवं राज्य वित्त के धनराशि का सही सदुपयोग करें, जो भी कार्य कराए मानक गुणवत्ता, पारदर्शिता के अनुरुप कार्य। समीक्षा के दौरान नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा राज्य वित्त मद से 159 कार्य में से 133 कार्य पूर्ण होने की सूची उपलब्ध कराने हेतु ईओ भदोही को निर्देश दिया। साथ ही सभी कार्यों की जांच कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर निकाय के कार्यों की प्रगति समीक्षा के दौरान एमआरएफ योजना के अंतर्गत कार्य, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना अंतर्गत कार्य, वेंडिंग जोन , स्वच्छता कार्यक्रम, 15 वें राज्य वित्त/अन्य विकास कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की प्रगति व किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि व स्वीकृत कार्य, पेयजल आदि के अंतर्गत स्वीकृत करने, गौशाला निर्माण, गोवंश को पकड़कर गौशाला में स्थापित किए जाने की प्रगति के दृष्टिगत ड्रेनेज/जल निकासी की व्यवस्था, पं दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति के विभिन्न आयामों सहित प्रगति समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी आयामों पर बिन्दुवार गंभीरता से व ससमय योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश समस्त अधिशासी अधिकारियों को दिया।

उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में प्लास्टिक पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को अभियान चलाकर दुकानों पर छापेमारी कर प्लास्टिक जब्त करते हुए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी वि0 रा0 कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संतोष कुमार चक, समस्त अधिशासी अधिकारी, एलबीसी उपस्थित रहे।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अन्तर्गत 'सेवा पखवाड़ा' व मिशन शक्ति 5 के तहत किया गया कन्या पूजन

भदोही। जनपद में निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ/जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देश के क्रम में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अन्तर्गत 'सेवा पखवाड़ा' व मिशन शक्ति 5 के तहत आज दिनाक 22.09.2025 को मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल के अध्यक्षता में नवरात्र के शुभ अवसर पर डायट परिसर, ज्ञानपुर में 21 बालिकाओं का कन्या पूजन, 11 बालिकाओं का कन्या जन्मोत्सव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रम में महिला शक्ति हेतु जागरूकता कार्यक्रम किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 21 कन्याओं को तिलक पूजन करते हुये टोपी, चुनरी , फल, मिठाई, पेन, भोजन प्रसाद एवं उपहार इत्यादि भेंट किया गया। 11 बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाते हुए केक काटकर उन्हें बेबी किट व पोषण पोटली भेट किया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं और उनका योगदान हमारे समाज के विकास में अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी होगी ताकि हम एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण कर सकें।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने केंद्र व प्रदेश सरकार बालिकाओं एवं महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की महिलाएं, बेटियां देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना व अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज में बेटी और बहू के बीच का भेदभाव खत्म होगा एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य), पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेन्टर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाईन एवं टोलफ्री नं0-181 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 06 श्रेणियों लाभ प्रदान किया जाता है।

प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पर 5000/- द्वितीय श्रेणी बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 2000/- तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश पर 3000/- चतुर्थ श्रेणी कक्षा छः में बालिका के प्रवेश पर 3000/- पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश पर 5000/- एवं षष्ठम् श्रेणी बालिका द्वारा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर 7000/- प्रदान किया जाता है। जनपद में कुल 18570 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

क्रार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन से राजकुमार गुप्ता, ममता सिंह, रेशमा भारती, प्रियंका गुप्ता, आनन्द कुमार मौर्या, आलोक दूबे एवं शिक्षिका व काफी संख्या में छात्रायें उपस्थित रहीं।

इफको नैनो उर्वरक जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय कृषक गोष्ठी में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के प्रयोग वधि एवं लाभ की दी गई जानकारी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जनपद में विकास खंड अभोली के ग्राम पंचायत वीरभद्रपट्टी में नैनो उर्वरकों पर आधारित विकास खंड स्तरीय कृषक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक कृषि अधिकारी, अभोली, गोविन्द लाल यादव, टीएसी अनुज मौर्य और कृषि सलाहकार रामेश्वर सिंह थे।

क्षेत्र अधिकारी इफको भदोही विमल कुमार जायसवाल द्वारा किसानो को किसानो को नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस के प्रयोग विधि एवं लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । नैनो डीएपी के 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधन एवं 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से जड़ शोधन करने के बाद आधा घंटा सुखाए उसके बाद बुवाई/रोपाई कर दे एवं जब फसल में पत्तियां आ जाए तो नैनो यूरिया प्लस या नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का एक साथ 4 मिलीलीटर / लीटर के दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करे। द्वितीय यूरिया टापड्रेसिंग में सभी किसान भाई दानेदार यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का छिड़काव अत्याधिक प्रयोग से जल, मृदा एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी अवगत कराया गया ।

आगामी रबी सीजन में सभी किसान भाई मुख्य फसलों गेहूं, सरसों, आलू, चना , मटर में नैनो डीएपी से बीज शोधित कर बुवाई करे एवं दानेदार डीएपी की मात्रा आधी

पत्तियों पर करे ।नैनो उर्वरकों के प्रयोग से कृषकों के लागत में भी कमी आएगी साथ ही यूरिया एवं डीएपी के प्रयोग करे ।नैनो डीएपी 500 मिलीलीटर की बोतल से 100 किलोग्राम बीज को शोधित कर सकते है एवं मात्र 600 रूपये की है जो कि दानेदार डीएपी से काफी सस्ता है। नैनो डीएपी के प्रयोग से लागत में कमी आएगी साथ ही उत्पादन के साथ उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

सहायक कृषि अधिकारी द्वारा सभी कृषकों को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करते हुए नैनो डीएपी से बीज शोधित कर बुवाई करने एवं पत्तियां आने पर नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का पत्तियों पर छिड़काव करने से पैदावार बढ़ती है साथ ही नैनो उर्वरकों के प्रयोग से लागत में भी कमी आती है ।

कृषकों को संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग के साथ नैनो तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया एवं दानेदार उर्वरकों पर भारत सरकार द्वारा दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी से भी अवगत कराया गया । सभी कृषकों को नैनो डीएपी से बीज शोधित कर बुवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया । नैनो डीएपी से शोधन कर बुवाई करने पर बीजों का जमाव अच्छा होने के साथ जड़ो का विकास भी अच्छा होता है और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह द्वारा गेहूं एवं धान की फसल में नैनो उर्वरक के प्रयोग को लेकर अपना अनुभव साझा किया । गेहूं की फसल में नैनो डीएपी से बीज शोधित कर बुवाई की और पत्तियां आने पर नैनो उर्वरकों का छिड़काव किया इससे पैदावार भी अधिक हुई साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ी।

साइबर क्राइम पुलिस द्वारा शेयर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड की धनराशि कराया गया वापस

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जनपद में हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम हेतु अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना को किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ हुए धोखाधड़ी या सोशल साइट के दुरुपयोग पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त के क्रम में आवेदक मनोज कुमार पुत्र तुलसी राम निवासी हरिहरपुर उर्फ शुकुलपुर ज्ञानपुर भदोही के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर 316000 रुपए का फ्रॉड की आनलाइन शिकायत की थी ।

साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा उक्त एनसीआरपी को रिपोर्ट प्रेषित किया गया तथा मिली जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना बृजेश सिंह व का0 कन्हैया कुमार सिंह, म0का0 नैंसी यादव द्वारा ?77000/-(सत्तर हज़ार रु0) की धनराशि को पीड़ित के खाते में वापस कराया गया । पीडित द्वारा अपने खाते से गयी धनराशि को वापस पाकर पुलिस अधीक्षक भदोही व साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भदोही पुलिस की भूरि- भूरि प्रशंसा की गयी ।

75 करोड़ की लागत से बनी सड़क हाथ लगाते ही उजड़ने लगी

नाराज विधायक ने ठेकेदार और अधिकारियों को लपेट दिया

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के हरदोई में 75 करोड़ की लागत से दो माह पूर्व बनी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक उस समय हैरान हो गए जब उनके हाथ लगाते ही सड़क उखड़ने लगी। जिसके बाद उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक द्वारा हाथ से सड़क उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह सड़क बघौली से प्रताप नगर तक लगभग 16 किलोमीटर की बनी है क्षेत्रीय विधायक प्रभाष कुमार के हाथ लगते ही सड़क उखड़ने लगी जिसके बाद विधायक जी का पारा हाई हो गया और तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी को फोन कर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सांडी विधान सभा क्षेत्र में बघौली से प्रताप नगर तक लगभग 16 किलो मीटर तक दो महा पूर्व बनी इस सड़क का विधायक द्वारा सड़क उखड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

हालांकि यह सड़क इससे पहले काफी जर्जर थी इसके निर्माण के लिए यहां के लोगों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और कई बार आंदोलन चलाये थे इसमे गड्ढे इतने थे कि उसमें घुटनों तक पानी भर जाता था तो लोगों ने इसका विरोध भी किया था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक प्रभाष कुमार से रविवार को की थी जसके बाद वह निरीक्षण करने पहुंचे तो विधायक जी ने जैसे ही सड़क पर हाथ लगाया वह उखड़ने लगी। विधायक ने तुरन्त पीडब्ल्यूडी अभियंता को फोन लगाया और नाराजगी जाहिर की।

विधायक प्रभास कुमार ने बताया कि यह बघौली से प्रताप नगर मार्ग है लगभग 16 किलोमीटर है जो नैमिष को छूता है और यह 75 करोड़ की लागत से स्वीकृति मिली थी और कल क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने शिकायत की थी और मैं खुद मौके पर गया और पाया। यह दो महीने पहले ही परिपूर्ण हुई है लेकिन वहां पर मैं गया तो मैंने देखा की बहुत सी जगह बजरी उखड़ गई है और पुलिया जो बनी है। वह सब धस चुकी है मैं मौके से डीएम और विभागीय अधिकारियों से बात की है और कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार और कुछ अधिकारियों की संलिप्ता नजर आती है जिसकी वजह से गुणवत्ता में कमी आई है और मैंने ऊपर तक सूचित कर दिया है अधिकारियों ने आश्वासन दिया है की जो भी होगा इसमें दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

'आई लव मोहम्मद' के जुलूस में लगे 'सर तन से जुदा' करने के नारे, महिलाएं छीनने लगीं पुलिस की लाठियां, मची भगदड़

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के बाद उपजा तनाव अब उन्नाव पहुंच गया। रविवार रात गंगाघाट क्षेत्र के मनोहर नगर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने जब रोक लगाई, तो हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया और कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह की वर्दी तक फाड़ दी। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने धार्मिक नारे लगाए और जुलूस को दुर्गा मंदिर के पास से निकालने का प्रयास किया। इस दौरान 'सर तन से जुदा' जैसे आपत्तिजनक नारे लगने पर पुलिस लाठी चार्ज कर दिया।

बता दें कि रविवार रात करीब 8:45 बजे मनोहर नगर में 'द थ्दन मोहम्मद' के समर्थन में पुरुषों और महिलाओं की भारी भीड़ ने जुलूस निकाला। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोका, लोग उग्र हो गए और 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजाष्ठ' , सर तन से जुदा करने

जैसे नारे लगाने लगे। जब कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, तो प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और उनकी वर्दी के स्टार तक नोच लिए।

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए गंगाघाट, सदर और अचलगंज कोतवाली से अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया। क्विक रेस्पॉन्स टीम और पीएसी जवान भी मौके पर पहुंचे। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई। भीड़ में मौजूद महिलाओं ने जब पुलिस को रोकने की कोशिश की, तो बहस भी हुई।

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, बवाल की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल हुए भड़काऊ पोस्ट से हुई। उसी के विरोध में लोग जुलूस निकालने सड़कों पर उतरे। पुलिस का कहना है कि यह जुलूस बिना किसी अनुमति के निकाला गया था। एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में धारा 163 लागू की गई है। छह लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

इस पूरे मामले की जड़ें कानपुर के रावतपुर इलाके से जुड़ी हैं, जहां 4 सितंबर को बारावफात के मौके पर 'द थ्दन मोहम्मद' का साइन बोर्ड लगाया गया था। अगले दिन कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इसे नई परंपरा बताया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों समुदायों में नारेबाजी और टकराव हो गया। ईद्दं दर्ज होने के बाद मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताते हुए कई शहरों में जुलूस निकाले। शारदानगर में लोग ईद्दं वापस लेने की मांग करने लगे।

मकान टूटने के भय से गरीब युवक ने दे दी जान

भाजपा विधायक ने वन विभाग और प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के एटा जिले के मलावन क्षेत्र में रविवार को कथित रूप से मकान तोड़े जाने के डर से एक गरीब व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। क्षेत्रीय विधायक विपिन कुमार वर्मा ने बिना वैकल्पिक ठिकाना उपलब्ध कराये व्यक्ति का मकान तोड़ने की तैयारी किये जाने का आरोप लगाते हुए इस वारदात के लिये वन विभाग और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि मलावन थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव में हरि सिंह नामक 35 वर्षीय एक व्यक्ति ने रविवार को एक पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक हरि सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था और गांव में पिछले 25 वर्षों से दो कमरे का मकान बनाकर उसमें परिवार के साथ रहता था। वन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के बाद उसके मकान को तोड़ने की तैयारी की जा रही थी। इसी दबाव से भयभीत होकर हरि सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर एटा सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विपिन कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और सिंह के

परिजन के प्रति संवेदना प्रकट की।

विधायक ने हरि सिंह की आत्महत्या के लिये वन विभाग और प्रशासन को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी पंचायत कर वन विभाग से आग्रह किया था कि 25 वर्ष पुराने मकान को तोड़ने से पहले गरीब परिवार को कहीं और बसाने के लिए मकान उपलब्ध कराया जाए।

इस पर विभाग ने आश्वासन भी दिया था लेकिन इसके बावजूद लगातार मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था जिससे हरि सिंह तनाव में आ गया। उन्होंने कहा कि अगर गरीब की समस्या का समय रहते समाधान किया गया होता तो यह घटना न होती। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज कराने और कार्रवाई कराने की बात कही है।

अधिक बारिश होने की वजह से फसल हो गई बर्बाद, बर्दाशत नहीं कर पाया किसान, फांसी लगाकर दे दी जान

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मैनपुरी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर बीते दिनों हुई ज्यादा बारिश की वजह से एक किसान की धान की फसल बर्बाद हो गई। इससे किसान बहुत दुखी हो गया, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखीर उसने मौत का ही रास्ता चुन लिया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला।

बता दें कि किशनी के गांव परतापुर के रहने वाले किसान का शव रविवार सुबह पेड़ पर फंदे से लटका मिला। दरअसल, 42 साल

के उमेश यादव ने इस बार धान की फसल की थी, फसल तैयार हो चुकी थी। कटाई हो पाती, इससे पहले ही बारिश में फसल बर्बाद हो गई। शनिवार की रात को उमेश खेत पर रखवाली के लिए गए थे। रविवार की सुबह परिजन को सूचना मिली कि उनका शव खेत में लगे पाकर के पेड़ पर फंदे से लटका हुआ है।

जब परिवार वालों को उनकी मौत की खबर मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में भी हड़कंप मच गया। जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं, एसडीएम किशनी गोपाल शर्मा ने बताया कि लेखपाल को भेजकर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को संभावित सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध

एफआईआर और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट

लखनऊ **(एजेंसी)**। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार नेराज्य में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक स्थानों, आधिकारिक प्रारूपों और वाहनों से जाति-आधारित संदर्भों को हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक आधिकारिक आदेश में सभी राज्य विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गिरफ्तारी ज्ञापन, प्राथमिकी या किसी अन्य पुलिस दस्तावेज़ में जातियों का उल्लेख न हो। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि पुलिस नोटिसबोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड पर प्रदर्शित जाति-आधारित संदर्भों को भी हटा दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के माता-पिता के नाम का उपयोग 'पहचान' के लिए किया जा सकता है। इस आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस नियमावली और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में भी संशोधन करेगी। राज्य सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड से जाति-आधारित संदर्भों को हटाने का आदेश तो दिया है, लेकिन कुछ छूट भी दी है। राज्य सरकार के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने वाले मामलों में छूट दी गई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 सितंबर के अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख करने की प्रथा को रोकने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस प्रथा को कानूनी भ्रांति करार देते हुए कहा कि यह संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है और संवैधानिक लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों की जाति माली, पहाड़ी, राजपूत, ठाकुर, पंजाबी पाराशर और ब्राह्मण के रूप में दर्ज करने से कोई वैध या उचित उद्देश्य पूरा नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विभागीय जाँच की सिफ़ारिश करने या अधिकारी को संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक सरोकारों के बारे में जागरूक करने के बजाय, उनके आचरण का बचाव अस्पष्ट और असंतुलित आधारों पर किया गया।

कमल हासन का विजय को संदेश : भीड़ हमेशा वोटों में नहीं बदलती, हर नेता के लिए हकीकत

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) प्रमुख कमल हासन ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक रैलियों में उमड़ी भीड़ को वोट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह सच्चाई तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय समेत सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होती है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक परामर्श बैठक के बाद चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए, हासन ने कहा कि यह निश्चित है कि सभी वोटों में तब्दील नहीं होंगे। यह सभी नेताओं पर लागू होता है।

जब उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि क्या उनकी टिप्पणी अभिनेता-राजनेता विजय के लिए थी, तो हासन ने स्पष्ट किया कि यह एक सामान्य टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि जब यह सभी नेताओं पर लागू होता है, तो हम विजय को कैसे बाहर कर सकते हैं? यह मुझ पर और भारत के हर नेता पर लागू होता है। आप भीड़ तो खींच सकते हैं, लेकिन वह सब वोटों में नहीं बदलेगी। टीवीके प्रमुख के लिए क्या उनके पास कोई सलाह है, इस पर हासन ने कहा, 'सही रास्ते पर चलें, साहस के साथ आगे बढ़ें और लोगों का भला करें। यह मेरी सभी नेताओं से अपील है।'

राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि आलोचना सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है, और यहाँ तक कि सिनेमा के महत्वाकांक्षी कलाकार भी इससे अछूते नहीं हैं। हासन की यह टिप्पणी डीएमके और अन्य दलों की इस आलोचना के बीच आई है कि विजय की रैलियों में भारी भीड़ का चुनावी समर्थन में तब्दील होना ज़रूरी नहीं है। हाल ही में, विजय ने एक रैली में अपने 'अनुयायियों से ईमानदार बने रहने, लोगों के लिए काम करने और सही तरह के नेतृत्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहने' का आग्रह किया था।

हासन, जिन्होंने 2018 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा, ने कहा कि अनुभव ने उन्हें दिखाया है कि 'भीड़ जुटाना केवल शुरुआत है, और निरंतर जमीनी स्तर पर काम ही अंततः वोटों का फैसला करेगा।' इस बीच, शनिवार को, टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे पर निशाना साधा और उन पर तमिलनाडु की प्रगति को रोकने का आरोप लगाया। तिरुवरुर में बोलते हुए, विजय ने राज्य के विकास की तुलना सत्तारूढ़ द्रमुक नेतृत्व द्वारा स्थिर छोड़े गए रथ से की।

शर्म आनी चाहिए : आरक्षण पर बयान देकर फंसी सुप्रिया सुले, विवाद बढ़ता देख संविधान का जिक्र कर दी सफाई

मुम्बई **(एजेंसी)**। जाति जनगणना और आरक्षण पर चल रही बहस पूरे भारत में विरोध और चर्चाओं को जन्म दे रही है। इस मुद्दे पर बोलते हुए, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ज़ोर देकर कहा है कि आरक्षण केवल जाति या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक ज़रूरतमंदों को दिया जाना चाहिए। सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। अब विवाद बढ़ता देख सुले ने आरक्षण पर अपने बयान को लेकर सफाई दी है। एक निजी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत स्पष्ट हूं कि हमें सबको बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखे संविधान का पालन करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ये देश संविधान पर चले। इसके साथ ही सुले ने पार्टी के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष राज राजापुरकर को सरकार से सुरक्षा देने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों एनडीटीवी के एक युवा कार्यक्रम में बोलते हुए, सुले ने कहा था कि आरक्षण पीढ़ी-दर-पीढ़ी हर जाति या समुदाय को नहीं दिया जाना चाहिए। यह उस बच्चे या परिवार को मिलना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि उनके अपने परिवार को आरक्षण के लाभ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके माता-पिता शिक्षित थे और उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ़ इसलिए आरक्षण की हक़दार हूँ क्योंकि मैं एक जाति से हूँ, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। एक दूरदराज के गाँव में सीमित संसाधनों वाले लेकिन असाधारण प्रतिभा वाले बच्चे को मुंबई के शीर्ष स्कूलों में पढ़ने वाले मेरे बच्चे से कहीं ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है।

सुले ने आरक्षण प्रणाली में सुधारों का आह्वान करते हुए कहा कि इसमें जातिगत पहचान के बजाय आर्थिक कमज़ोरी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि वास्तव में योग्य बच्चों और परिवारों को समान अवसर मिल सकें। सुले की यह टिप्पणी कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के मराठों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के कुछ दिनों बाद आई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी अधिकांश माँगें मान लेने के बाद, जिनमें पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है, उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपना आंदोलन वापस ले लिया था, जिससे वे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलने वाले आरक्षण लाभों के पात्र बन जाएँगे।

उमर खालिद-शरजील इमाम केस में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। पिछले पाँच सालों से जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और आठ अन्य को इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साज़िश से जुड़े एक आतंकवाद-रोधी कानून से जुड़ा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने खालिद, इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद द्वारा दायर सभी ज़मानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने इमाम और खालिद की दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला प्रथम दृष्टया गंभीर प्रतीत होता है और दोनों ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए भाषण दिए थे। आदेश में कहा गया है, अगर विरोध करने के अप्रतिबंधित अधिकार के प्रयोग की अनुमति दी गई, तो यह संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुँचाएगा और देश की कानून-व्यवस्था को प्रभावित करेगा। नागरिकों द्वारा विरोध या प्रदर्शन की आड़ में किसी भी षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाइयों को राज्य मशीनरी द्वारा नियंत्रित और नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति, भाषण और संघ बनाने की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आतीं।

मुंबई में दुर्गा प्रतिमा खंडित, गरमाया माहौल! दो गुटों में झड़प के बाद 7 गिरफ्तार

मुम्बई **(एजेंसी)**। मुंबई के मानखुर्द में देवी दुर्गा की प्रतिमा कथित तौर पर खंडित होने के बाद दो समूहों में झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप तनाव फैल गया और पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया। यह घटना नवरात्रि की पूर्व संध्या पर हुई, जब एक समूह ने प्रतिमा खंडित पाई और दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि मुंबई में देवी दुर्गा की एक मूर्ति को कथित तौर पर अपवित्र किए जाने के बाद तनाव बढ़ गया, जिसके बाद दो समूहों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने बताया कि रविवार रात मानखुर्द इलाके में हुई इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, मानखुर्द पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नवरात्र की पूर्व संध्या पर देवी की प्रतिमा को एक संकरी गली से ले जाया जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने पाया कि प्रतिमा खंडित है तथा इसके लिए दूसरे समूह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके साथ बहस शुरू कर दी।

अधिकारी ने बताया कि दोनों समूहों के बीच झड़प हुई और उन्होंने एक-दूसरे पर हमला किया। बाद में, पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार सात लोगों के खिलाफ मारपीट और गैरकानूनी रूप से एकत्र होने सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संबंधित समूह हर साल नवरात्र उत्सव मनाता है। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच जारी है।

कांग्रेस का तंज : हमारा जीएसटी विचार अब भाजपा ने माना, गब्बर सिंह टैक्स को सुधारा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। जीएसटी सुधार को लेकर कांग्रेस कई सवाल खड़े सरकार से कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह जीएसटी की भावना कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की थी। हमारा उद्देश्य पूरे देश में जीएसटी लागू करना था और इसे कई स्लैब में नहीं, बल्कि 1-2 स्लैब में लागू करना था ताकि आम नागरिकों को रोज़गार पाने में ज़्यादा दिक्कत न हो। हमारी भावना को उधार लेते हुए, भाजपा ने बहुत ढिंढोरा पीटकर जीएसटी लागू किया।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस जीएसटी का उद्देश्य करों को सरल बनाना था, उसे इस एनडीए सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स में बदल दिया। स्लैब कम करने की जो मांग सदन के अंदर और बाहर बार-बार की गई थी, वह अब पूरी हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध किया था।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव रमेश ने एएनआई को बताया कि 2006 से 2014 तक, आठ साल तक, केवल एक मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया, और वह मुख्यमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2017 में यू-टर्न लेते हुए जीएसटी के मसीहा के रूप में उभरे। उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में घोषित जीएसटी सुधार सीमित हैं क्योंकि वे एमएसएमई क्षेत्र की प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने में आसानी प्रदान नहीं करते हैं। जीएसटी में हालिया सुधार सीमित हैं। एमएसएमई क्षेत्र की प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है।

रमेश ने कहा कि जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव सबसे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2006 में पेश किया था और 2010 में इसे विधेयक के रूप में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए, तो सरकार कर ढांचे में सुधार करने के लिए मजबूर हुई और अब वे इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। वे आठ साल देर से आए हैं। जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव सबसे पहले 2006 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रखा था। 2010 में इसे संसद में विधेयक के रूप में पेश किया गया था।

पाक क्रिकेटर हारिश रऊफ की शर्मनाक हरकत! मैदान में उड़ाया ऑपरेशन सिंदूर का मजाक

आईएएफ पर इशारा कर भारतीय फैंस को उकसाया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। 21 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों को विवादित 6-0 का इशारा करते हुए देखे गए। बाउंड्री के पास फील्डिंग करते हुए रऊफ द्वारा भारतीय प्रशंसकों को 6-0 का इशारा करते हुए कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। 6-0, पाकिस्तान के उस निराधार दावे का संदर्भ है जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चार दिनों तक चली झड़प के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था।

भारत के खिलाफ मैच में, जिसमें पाकिस्तान 171 रनों के कुल स्कोर का बचाव करने में विफल रहने के बाद 6 विकेट से हार गया था, रऊफ ने चार ओवर फेंके और 26 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को तीन गेंदों पर शून्य पर आउट करके अपना विकेट खाता खोला और फिर संजू सैमसन का विकेट लिया। रन चेज़ के 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर अबरार अहमद ने सूर्या का कैच लपका, जबकि रऊफ़ ने सैमसन की रक्षापंक्ति को भेदते हुए 17 गेंदों में 13 रन भारत के कुल स्कोर में जोड़े।

बाउंड्री के पास क्षेत्ररक्षण करते समय, रऊफ़ को 'विराट कोहली' के नारे लगाने पड़े, क्योंकि प्रशंसक उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 2022 के मुकाबले की याद दिला रहे थे, जहाँ भारतीय बल्लेबाज़ ने आखिरी से पहले वाले ओवर में उन पर लगातार 2 छक्के जड़कर पासा पलट दिया था।

हालांकि, रऊफ़ ने इसके बाद जो किया वह बेहद उत्तेजक था। पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ ने प्रशंसकों की ओर '6-0' का इशारा किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के उन अपुष्ट दावों का ज़िक्र किया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य संघर्ष के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। 6-0 के इशारे के बाद, रऊफ़ ने विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की नकल करते हुए हाथ के इशारे भी किए।

दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की पूर्व संध्या पर सलमान अली आगा की टीम के एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान भी 6-0 के संकेत सामने आए। यह तब हुआ जब पाकिस्तानी टीम एक फुटबॉल मैच खेल रही थी, जिसमें एक टीम ने 6-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 6-0, 6-0... चिल्लाना शुरू किया, खासकर मैदान पर मौजूद भारतीय पत्रकारों की मौजूदगी में, उससे कई लोगों को समझ आ गया कि उनका इरादा कुछ और ही था। जहाँ पाकिस्तान और उसके कई पूर्व खिलाड़ी कहते हैं कि राजनीति और खेल एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होने चाहिए, वहीं हारिस रऊफ़ जैसे खिलाड़ियों की मैदान पर की गई हरकतें सीमा पार के क्रिकेटरों की असल भावनाओं को कुछ और ही बयां करती हैं।

भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच की बात करें तो, एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव की टीम ने पाकिस्तान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाती हैं तो भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में एक बार फिर आमने-सामने हो सकते हैं।

एशिया कप 2025 फाइनल हो सकता है भारत-पाक के बीच? बन रहा ऐसा समीकरण

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक नहीं बल्कि दो बार करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। पहले लीग स्टेज मुकाबले में और फिर सुपर-4 मुकाबले में 6 विकेट से पाकिस्तान को भारत ने परास्त किया है। इस हार के चलते पाकिस्तानी टीम की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, पाकिस्तानी टीम के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका है। बाकी दोनों मैच जीतकर वो फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को काफी मजबूत कर सकता है।

एशिया कप में सुपर-4 में पहुंचने वाली चारों टीमों को 3-3 मुकाबले खेलने हैं। अगर पाकिस्तान अब अगले दो सुपर- 4 मुकाबले जीत लेता है तो उसके चार अंक हो जाएंगे। ऐसे में अगर वो अंकतालिका में टॉप-2 में रहेगा, तभी फाइनल खेल पाएगा। वहीं भारतीय टीम के साथ भी यही स्थिति रहेगी। टीम इंडिया को भी खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए टॉप-2 में जगह बनानी होगी।

फिलहाल, सुपर-4 में पहुंचने वाली चार टीमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है। वहीं बुधवार 24 सितंबर को भारत बांग्लादेश से टकराएगा। जबकि उसके बाद शुक्रवार को वो श्रीलंका से भिड़ेगा। अगर भारत इनमें से एक भी मैच जीतता है तो भी वो फाइनल में पहुंच सकता है। हालांकि, ऐसे में उसका रन रेट पर मामला अटक सकता है। अगर टीम इंडिया बाकी दोनों मैच जीतती है तो उसका फाइनल खेलना पूरी तरह तय रहेगा। तब नेट रन रेट की चिंता भारतीय टीम को नहीं करनी होगी।

पाकिस्तान टीम अगर अपने अगले मुकाबले में 23 सितंबर को श्रीलंका से हार जाती है तो उसका बाहर होना लगभग तय हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश से जीतकर भी वो ज्यादातर 2 अंक ही जुटा पाएगा। अगर पाकिस्तान श्रीलंकाई टीम को हरा देता है तो फिर उसे फाइनल की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ जीत चाहिए होगी। श्रीलंका और बांग्लादेश भी फाइनल की रेस में बनी हुई हैं।

श्रीलंका ने ग्रुप-बी में तीनों मैच जीते थे लेकिन सुपर-4 के पहले मैच में उसे बांग्लादेश ने हरा दिया। अगर बांग्लादेश के पास पहले से एक जीत है और उसके दो अंक हैं। भारत के पास भी दो अंक हैं और वो बेहतर नेट रनरेट के कारण पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे पर श्रीलंका और चौथे पर पाकिस्तान टीम है।

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान का फाइनल भी संभव है। अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतती है जबकि भारत भी अपने दोनों मैच जीतता है तो दोनों देश एशिया कप 2025 में तीसरी बार भिड़ेंगी। टीम इंडिया ने अगर एक मैच गंवाया जबकि पाकिस्तान टीम अपने बाकी मैच जीतती है तो भी दोनों के बीच फाइनल मुकाबला हो सकता है। हालांकि, ऐसे में नेट रन रेट भी अहम भूमिका निभाएगा।

बेशर्मी की हद : पहले आतंकी इशारे किए फिर कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता

पाकिस्तानी साहिबजादा फरहान ने दिया ये घिनौना बयान

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। बार-बार भारत के हाथों हार मिलने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते पाकिस्तान खिलाड़ी। एशिया कप 2025 में लगातार दूसरी बार हार झेलने के बाद भी बेशर्मी दिखा रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी। पाकिस्तान को भारत की धमाकेदार जीत का जश्न दुनियाभर में मौजूद हिन्दुस्तानी फैंस मना रहे हैं। भारतीयों के भीतर पाकिस्तान को हराने का जितनी खुशी है उतना ही गुस्सा भी है। पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान के गन स्टाइल सेलिब्रेशन पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है।

भारतीय फैंस का कहना है कि इस गन सेलिब्रेशन से साहिबजादा फरहान पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों को कुरेदना चाहते थे। मैच के दौरान ये घटिया हरकत करने वाले साहिबजादा फरहान अब घिनौना बयान देकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साहिबजादा फरहान ने कहा कि, मुझे लगता है कि अगर आप छक्कों की बात करें तो आप भविष्य में ऐसा देखेंगे। और वह (जश्न) उस समय बस एक पल था। मैं 50 रन बनाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आयो कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मैंने वैसे ही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह भी नहीं है और बाकी आप जानते हैं। आपको जहां भी खेलना है आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए। जरूरी नहीं कि वह भारत ही हो। आपको हर टीम के खिलाफ आक्राम क्रिकेट खेलना चाहिए जैसा हमने आज खेला।

वहीं श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की आगे की क्या रणनीति होगी इस पर उन्होंने कहा कि टीम ने पहले पावरप्ले में काफी विकेट गंवाए थे। इसमें सुधार करना जरूरी है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पहले 6 ओवर्स में रन बनाए जाएं।

रिजर्व बैंक ने दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनियमित ऋण देने की गतिविधियों के कारण नयी दिल्ली स्थित दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण संचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। इस कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।

कंपनी ने ग्राहकों की सोर्सिंग, उनकी उचित जांच-पड़ताल, कर्ज का वितरण, कर्ज अदायगी, दिए गए कर्ज की वसूली और साथ ही केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) सत्यापन जैसी प्रमुख सेवाओं को आउटसोर्स करके मानदंडों का उल्लंघन किया है। किन कैश ऐप और 'दोलोन ऐप' (जेस्ट टॉप वन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लि.) और जेस्ट कैश ऐप (कंपनी का ऐप) सेवा प्रदाता हैं। आरबीआई ने कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद, कंपनी अब किसी तरह का गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) का कामकाज नहीं कर पाएगी।

पहले क्रिकेट और अब फुटबॉल में पिटा पाकिस्तान भारत ने टी-सेलिब्रेशन की निकाली हवा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पहले भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर पस्त किया और अब फुटबॉल में भी भारत की अंडर-17 टीम ने पाकिस्तान को नहीं बख्शा। सोमवार, 22 सितंबर को कोलंबो में खेले गए सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप मुकाबले में भारत की टीम ने पाकिस्तान अंडर-17 टीम को हरा दिया। दल्लुलमुआन गांगटे, गुनलेइबा वांगकेइराक्पम और रहान अहमद के गोलों की बदलौत भारत को बेहतरीन जीत मिली। जिसके बाद ग्रुप बी में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की। इस मुकाबले में भी पाक खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों ने उकसाने की कोशिश की।

दरअसल, ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच रोमांचक रहा और पाकिस्तान के बराबरी के गोल के बाद हुए सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं। गांगटे ने 31वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई थी। लेकिन 12 मिनट बाद मोहम्मद अब्दुल्ला ने पेनल्टी से गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक अनोखा सेलिब्रेशन किया। अब्दुल्ला कॉर्नर पर जाकर बैठ गया और चाय पीने का इशारा किया।

वहीं कई लोगों ने इस सेलिब्रेशन को उकसाने वाला बताया लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले को जीतकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जवाब दिया।

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। 63वें मिनट में वांगकेइराक्पम ने बेहतरीन गोल दागकर भारत को फिर बढ़त दिला दी। हालांकि, सात मिनट बाद पाकिस्तान ने हमजा यासिर के गोल से फिर बराबरी की। लेकिन 73वें मिनट में अहमद के निर्णायक गोल ने भारत को जीत दिला दी।

वायदा बाजार में सोने का भाव 799 रुपये चढ़कर 1.11 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों के ताजा सौदों से वायदा कारोबार में सोने का भाव सोमवार को 799 रुपये चढ़कर 1.11 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों की कीमत 799 रुपये यानी 0.72 प्रतिशत चढ़कर 1, 11, 750 प्रति 10 ग्राम हो गई।

हालांकि, सबसे अधिक कारोबार करने वाले अक्टूबर आपूर्ति वाले अनुबंधों में सोने का भाव 761 रुपये या 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1, 10, 608 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले सप्ताह यह 1, 10, 666 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंचा था। चांदी में भी तेजी देखी गई और यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई।

अगले साल मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 2, 446 रुपये या 1.86 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1, 33, 582 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसी तरह, दिसंबर में आपूर्ति वाले सबसे अधिक कारोबार वाले चांदी के वायदा अनुबंध की कीमत 2, 473 रुपये या 1.9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1, 32, 311 रुपये प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए।

कारोबारियों का कहना है कि रुपये में कमजोरी और घरेलू बाजार में निराशाजनक माहौल ने सोने की कीमतों को और मजबूती दी। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 0.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3, 732.62 डॉलर प्रति औंस रहा। इस बीच, दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा भाव 2.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 43.88 डॉलर प्रति औंस रहा।

ऑक्शन से पहले हॉकी इंडिया लीग को बड़ा झटका, एक सीजन बाद हटी यूपी रूद्राज फ्रेंचाइजी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। हॉकी इंडिया लीग यानी [illegible] को बड़ा झटका लगा है। वित्तीय स्थिरता को लेकर हॉकी इंडिया के साथ हुए मतभेदों के बाद उत्तर प्रदेश की फ्रेंचाइजी यूपी रुद्रास लीग से हट गई है। इस फ्रेंजाइजी ने ये फैसला सिर्फ एक सीजन खेलने के बाद लिया है। वहीं बता दें कि, 24 सितंबर को इस सीजन के लिए मिनी ऑक्शन से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 24 सितंबर को होने वाली मिनी नीलामी से कुछ दिन पहले ही फ्रेंचाइजी ने ये फैसला लिया। जिसकी जानकारी उसने हॉकी इंडिया को दी।

बता दें कि, जेके सीमेंट्स के स्वामित्व वाली यूपी रुद्रास इस साल की शुरुआत में नए सिरे से तैयार किए गए हॉकी इंडिया लीग के पहले सीजन में पांचवें स्थान पर रही। इस टीम में कई शीर्ष भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल थे। जिनमें भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह, हाल ही में संन्यास लेने वाले फॉरवर्ड ललित उपाध्याय, इंग्लैंड के सैम वार्ड, बेल्जियम के टैंगुई कोसिंस और नीदरलैंड्स के लार्स बाल्क शामिल थे। भारत और नीदरलैंड्स के पूर्व ट्रेनर पॉल वैन ऐस यूपी रुद्रास के कोच थे।

यूपी रुद्रास के हटने से जब तक कोई रिप्लेसमेंट टीम या नया मालिक नहीं मिल जाता तब तक पुरुष टूर्नामेंट में सात टीमें रह जाएंगी। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सीजन शुरू होने से पहले कोई समाधान निकल आएगा।

वहीं इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि, रुद्रास प्रबंधन ने हॉकी इंडिया से लीग के वित्तीय अनुमानों पर स्पष्टता न मिलने के बाद इसे स्थगित कर दिया। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक चलने वाले पहले सीजन में टीमों ने लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए जिसमें 7 करोड़ रुपये की फ्रेंचाइजी फीस, वेतन के रूप में 4 करोड़ रुपये और संचालन लागत शामिल थी।

रुपया शुरुआती कारोबार में पांच पैसे टूटकर 88.21 प्रति डॉलर पर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ पांच पैसे टूटकर 88.21 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.20 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद फिसलकर 88.21 प्रति डॉलर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की गिरावट दर्शाता है।

रुपया शुक्रवार को चार पैसे की बढ़त के साथ 88.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.77 पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 475.16 अंक की गिरावट के साथ 82, 151.07 अंक पर और निफ्टी 88.95 अंक फिसलकर 25, 238.10 अंक पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 67.12 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 390.74 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

रिया चक्रवर्ती ने जमानत मिलने के बाद जेल में किया था नागिन डांस, बताया क्लीन चिट मिलने पर कैसा था रिएक्शन

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ में काफी उथल-पुथल देखने को मिली। इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और 28 दिनों तक वहां रहना पड़ा। हालांकि, अब एक्ट्रेस को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। वहीं, हाल ही में 'जलेबी' एक्ट्रेस एनडीटीवी के एक इवेंट का हिस्सा बनीं, जहां उन्होंने जेल में बिताए अपने अनुभव के बारे में बात की और साथ ही यह भी बताया कि जब उन्हें क्लीन चिट मिली तो इस पर उनका रिएक्शन कैसा था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने जेल में नागिन डांस किया था।

इंटरव्यू में बात करते हुए रिया से पूछा गया कि अगर जेल में कोई फिल्म बन रही हो और वह खुद उसकी निर्देशक हों, तो वह किसे कास्ट करेंगी? इसके जवाब में अभिनेत्री ने कहा, 'मैं अपने किसी भी सहकर्मी के लिए ऐसी बदकिस्मती नहीं चाहूंगी। आपको कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल जिंदगी में कई हीरो और हीरोइन जेल गए और वापस आए हैं।'

बातें करते हुए रिया ने जेल के अनुभव भी शेयर किए। उन्होंने कहा, 'वहां आपको सब कुछ याद आता है कि आपके पास क्या था, जब आप सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि जेल में तो कुछ भी नहीं मिलता है। आप अपने माता-पिता को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वे आपसे पूछते रहते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं। जेल में आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। मुझे अपने परिवार की सबसे ज्यादा याद आती थी।'

एक्ट्रेस से जेल जाने के बाद क्या बदला इसके बारे में भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जेल जाने के बाद आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदल जाता है। आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इससे आपको डिप्रेशन जरूर होगा। आप लोगों की सोच से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, आप खाने की बहुत कद्र करने लगते हैं। घर का दाल-चावल भी पिज्जा जैसा नहीं लगता। आपको यह भी एहसास होता है कि दुनिया में आपके सिर्फ 3-4 दोस्त ही हैं, बाकी सब आपके दोस्त नहीं हैं।' बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने से पहले रिया चक्रवर्ती 28 दिनों तक जेल में रहीं। एक अभिनेत्री के तौर पर जेल में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया, 'लोगों ने मुझसे उनके लिए डांस करने को कहा। जमानत वाले दिन मैंने नागिन डांस किया। मैंने सोचा कि पता नहीं मैं उनसे अगली बार कब मिलूंगी और अगर मैं उन्हें खुशी के दो पल दे सकती हूं, तो क्यों न दूं? ऐसी अंडर-ट्रायल जेलों में ज्यादातर महिलाएं बेगुनाह और होपलेस होती हैं।'

सीबीआई द्वारा सभी आरोपों में क्लीन चिट मिलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'उस दिन मेरे घर में सब रोए थे। मैंने अपने भाई को गले लगाया और फूट-फूट कर रो पड़ी। जब मैंने अपने माता-पिता को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि हम सब हमेशा के लिए बदल गए हैं। अब हम पहले जैसे बेफिक्र परिवार नहीं रहे। उस पल ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया।'

रिया ने आगे कहा, 'जब मुझे क्लीन चिट मिली, तो मैं बहुत खुश नहीं थी। असल में, मुझे पता था कि मेरा कोई बहुत करीबी चला गया है और इसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे अपने माता-पिता के लिए राहत मिली। वे समाज में रहते हैं और लगातार लोगों का सामना करते हैं। उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। मुझे लगा कि शायद अब वे थोड़ा और आजादी से घूम-फिर सकेंगे।'

नवरात्रि के पहले दिन 'मर्दानी 3' का ऐलान रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय बनकर लौटीं!

रानी मुखर्जी मर्दानी 3 में शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दो किस्तों की सफलता के बाद, निर्माताओं ने 27 फरवरी, 2026 को तीसरे भाग की रिलीज की पुष्टि की। नवरात्रि के शुभ अवसर पर, निर्माताओं ने मर्दानी 3 के नए पोस्टर का अनावरण किया। पोस्टर में रानी को हाथ में बंदूक पकड़े देखा जा सकता है। इस अनावरण के साथ, अभिनेत्री 'अच्छे और बुरे' के बीच एक महाकाव्य लड़ाई के लिए तैयार हो गई है।

यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर मर्दानी 3 का नया पोस्टर शेयर किया है। इसे साझा करते हुए, निर्माताओं ने लिखा, नवरात्रि के शुभ दिन 1 पर, यहां बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी मुखर्जी अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण मामले की जांच करने के लिए मर्दानी 3 में शीर्ष पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट रही हैं। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 27 फरवरी, 2026 को।'

इससे पहले, एक आधिकारिक बयान में, अभिनेत्री ने खुलासा किया कि दर्शक मर्दानी 3 से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अप्रैल 2025 में मर्दानी 3 की शूटिंग शुरू कर रहे हैं! पुलिस की वर्दी पहनना और एक ऐसा किरदार निभाना हमेशा खास होता है जिसने मुझे हमेशा प्यार दिया है। मुझे मर्दानी 3 में इस साहसी पुलिस अधिकारी का किरदार फिर से निभाने पर गर्व है, जो उन सभी गुमनाम, बहादुर और आत्म-बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए हर दिन अथक परिश्रम करते हैं।'

प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित, मर्दानी की पहली किस्त 2014 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। इसकी बड़ी सफलता के बाद, दूसरी किस्त 2019 में सिनेमाघरों में आई। दूसरे भाग का निर्देशन गोपी पुथ्रन ने किया था।

'मर्दानी' फ़िल्में - भारतीय सिनेमा में एकमात्र महिला-पुलिस प्रधान फ्रैंचाइज़ी - अपनी प्रभावशाली कहानियों से लगातार प्रशंसकों के दिलों पर राज कर रही हैं और समाज के लिए एक आँख खोलने वाली कहानी का काम कर रही हैं। पहली फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी, जबकि दूसरी 2019 में आई थी। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निर्माताओं ने कहा, 'यह तीसरा अध्याय और भी गहरा और गंभीर होने का वादा करता है, जो दर्शकों को एक और भी रोमांचक नाटकीय अनुभव प्रदान करेगा।'

अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित, 'मर्दानी 3' 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। फिल्म के विषय के बारे में बात करते हुए, रानी मुखर्जी ने पहले कहा था कि 'मर्दानी 3' एक 'अद्भुत थ्रिलर' है जो 'अंधकारमय, घातक और क्रूर' है। निर्माताओं के अनुसार, फिल्म में शिवानी की अच्छाई और दुष्ट शक्तियों के बीच एक खूनी, हिंसक संघर्ष दिखाया जाएगा।

हवा में ही कॉकपिट का दरवाजा खोलने लगा यात्री

वाराणसी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में मच गया हड़कंप

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने बताया कि बेंगलुरु से वाराणसी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने शौचालय जाते समय कथित तौर पर कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। यात्री को कॉकपिट में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया गया और वाराणसी में उतरने पर अधिकारियों को सौंप दिया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि हमें वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान में हुई घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है, जहाँ एक यात्री शौचालय ढूँढ़ते हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में पहुँच गया। हम पुष्टि करते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता प्रोटोकॉल लागू हैं और उनसे कोई समझौता नहीं किया गया है। लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई थी और फिलहाल इसकी जाँच चल रही है।

जीएसटी राहत पर सियासी घमासान, ममता बोलीं- केंद्र को श्रेय नहीं, हमें हुआ नुकसान

कोलकाता **(एजेंसी)**। आज से संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के लागू होने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार की आलोचना की और कहा कि सारी राहत राज्य सरकारों के खजाने से आएगी, और केंद्र ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 25 पल्ली क्लब दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता। मैंने सबसे पहले पत्र लिखकर बीमा को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की थी। कई जीवन रक्षक दवाओं और छोटी वस्तुओं पर जीएसटी था। केंद्र सरकार ने इस राहत पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है; यह सब राज्य सरकारों के खजाने से आया है। वे श्रेय लेते हैं, लेकिन हमने इसकी कीमत चुकाई है।

ममता बनर्जी ने खुशी जताई कि लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन आरोप लगाया कि यह पैसा राज्य के जीएसटी हिस्से से काट लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्या वे हमारा पैसा लौटाएँगे? 100 दिनों के काम के लिए, आवास योजना के लिए, सड़कों के लिए, जल स्वप्न के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिएः सब कुछ ठप पड़ा है। और अब, फिर से, 20, 000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं ऐसी परिस्थितियों में राज्य कैसे चलाऊँगी? फिर भी, मुझे खुशी है कि लोगों को लाभ होगा। लेकिन कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है; यह पैसा बस हमारे जीएसटी हिस्से से काट लिया गया है। तथाकथित

'डबल इंजन सरकार' चुपचाप इसे गुप्त रास्तों से वापस ले लेगी।

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने रविवार को अगले जीएसटी सुधारों की आलोचना की और केंद्र को जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए मजबूर करने का श्रेय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को दिया, जिसे उन्होंने पहले 'जनविरोधी' करार दिया था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए, घोष ने कहा, 'जीएसटी दरें वास्तव में जनविरोधी थीं... क्योंकि लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं, इसलिए उस पर अधिक जीएसटी लगता है; स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अधिक जीएसटी लगता है। और जब सबसे अमीर लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं, तो जीएसटी कम लगता है, ' उन्होंने कहा।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ममता बनर्जी ने जीएसटी ढांचे के खिलाफ आवाज़ उठाई। घोष ने पूछा, 'ममता बनर्जी ने आवाज़ उठाई और फिर पूरा देश इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। केंद्र को जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वे इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी दरें शुरू ही क्यों कीं?' फिर उन्होंने कहा, 'क्योंकि आपकी दरें जनविरोधी थीं।' उन्होंने आगे कहा, 'इसका श्रेय ममता बनर्जी और एआईटीसी को जाता है कि उन्होंने खामियों को उजागर किया और उन्हें ये बदलाव करने के लिए मजबूर किया।'

वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में सुधार, जिसे इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में मंज़ूरी दी गई थी, आज से लागू होने वाला है। मौजूदा चार-दर प्रणाली को 5इ और 18इ की सुव्यवस्थित दो-स्लैब व्यवस्था से बदल दिया जाएगा। विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक अलग स्लैब रखी गई है।

तलाक के बाद पत्नी ने मांगे 5 करोड़ तो भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, दे डाली सख्त चेतावनी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक विवाह विच्छेद मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी चेतावनी दी, जब पत्नी ने एक साल पुरानी शादी तोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की। पीठ ने दोनों पक्षों को आगे की समझौता वार्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में लौटने का निर्देश दिया और आगाह किया कि अगर ऐसी मांगें जारी रहीं तो अदालत 'बेहद कठोर आदेश' जारी कर सकती है। पीठ ने गौर किया कि शादी को मुश्किल से एक साल ही हुआ था और पत्नी की ऊँची आर्थिक माँग पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पति के वकील से कहा, 'उसे वापस बुलाकर आप गलती कर रहे हैं। आप उसे अपने पास नहीं रख पाएँगे। सपने बहुत बड़े हैं। अगर आप उसे वापस बुलाते हैं, तो आप उसे वापस नहीं रख पाएँगे।

अदालत ने 5 करोड़ रुपये की मांग को अनुचित बताया और कहा कि ऐसा रुख प्रतिकूल आदेशों को आमंत्रित कर सकता है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि हम दोनों पक्षों को समझौते के लिए सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में वापस जाने का निर्देश देते हैं। हमें बताया गया है कि पत्नी ने विवाह विच्छेद के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की है। दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक जीवन लगभग एक वर्ष का ही है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने आगे कहा कि अगर पत्नी का रुख ऐसा ही रहा, तो हमें कुछ ऐसे आदेश देने पड़ सकते हैं जो उसे पसंद न आएँ। है ना? हम उम्मीद करते हैं कि पत्नी वाजिब माँग रखेगी और इस मुकदमे का अंत करेगी।

अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, अमेज़न में कार्यरत इंजीनियर पति ने कानूनी विवाद को समाप्त करने के लिए पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में 35 से 40 लाख रुपये की पेशकश की है। हालाँकि, पत्नी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को 5 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने को कहा है। मध्यस्थता रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी।

एमपी में नवरात्रि के लिए 2 अक्टूबर तक मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध

भोपाल **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रशासन ने नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लागू रहेगा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, भोपाल की अनुविभागीय मजिस्ट्रेट दिव्या पटेल ने बताया, 'नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी। इसे देखते हुए, शहर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच, गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर नवरात्रि के दौरान सभी मांस-मछली की दुकानें बंद करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों के पास की दुकानें श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं और नागरिकों को असुविधा होती है।

इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि कई दुकानें खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। विहिप के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र तंवर ने कहा कि प्रशासन से 'धार्मिक और जनभावनाओं का सम्मान' करने और मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है, साथ ही स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है।

बीजेपी सांसद की पत्नी हुईं डिजिटल अरेस्ट, 14 लाख गंवाए, पुलिस ने सारी रकम वापस दिला दी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। बेंगलुरु पुलिस ने चिक्कबल्लापुर के भाजपा सांसद और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डॉ. के. सुधाकर की पत्नी डॉ. प्रीति सुधाकर द्वारा खोए गए 14 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं। वे डिजिटल अरेस्ट नामक एक साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुई थीं। पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 26 अगस्त को 44 वर्षीय प्रीति को मुंबई साइबर क्राइम अधिकारी बनकर धोखेबाजों से एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। उन्होंने दावा किया कि उनका बैंक खाता अवैध अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से जुड़ा है और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने 'सत्यापन' वाले खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कॉल करने वालों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार 45 मिनट के भीतर पैसे वापस कर दिए जाएँगे। गिरफ्तारी के डर से, उन्होंने अपने एचडीएफसी बैंक खाते से 14 लाख रुपये एक अज्ञात यस बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।

प्रीति को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसने उसी शाम पश्चिम डिवीजन साइबर अपराध पुलिस स्टेशन का रुख किया। 'सुनहरे समय' में कार्रवाई करते हुए, जाँचकर्ताओं ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन 1930 पर मामला दर्ज कराने में उसकी मदद की और तुरंत प्राप्तकर्ता का खाता फ्रीज कर दिया। 3 सितंबर को, 47वीं एसीजेएम कोर्ट ने यस बैंक को फ्रीज की गई धनराशि वापस करने का निर्देश दिया। पूरी राशि एक सप्ताह के भीतर उसके खाते में वापस जमा कर दी गई। एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपी का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) गिरीश एस और सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम सेंट्रल इंजीनियरिंग) उमारानी एस ने इस अभियान का नेतृत्व किया। बेंगलुरु पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि वे ऐसी ही परिस्थितियों में एनसीआरपी हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके और बिना देर किए शिकायत दर्ज करके खोए हुए पैसे की वसूली की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें।

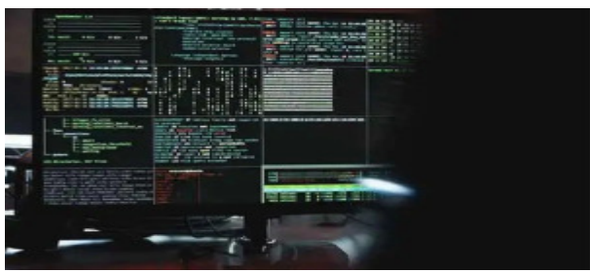

38 साल पुरानी परमाणु संधि तोड़ने के बाद अब रूस ने किया ऐसा ऐलान, ट्रंप भी हो जाएंगे खुश

मॉस्को **(एजेंसी)**। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ अपनी परमाणु संधि की समाप्ति के बाद भी मास्को अगले एक साल तक परमाणु हथियार सीमाओं का पालन करता रहेगा। न्यू स्टार्ट संधि दोनों देशों के बीच अंतिम सक्रिय हथियार नियंत्रण समझौता है। रूसी सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए पुतिन ने चेतावनी दी कि इस समझौते को समाप्त करने से वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने आगे कहा कि रूस उम्मीद करता है कि वाशिंगटन भी ऐसा ही करेगा और संधि की सीमाओं का सम्मान करेगा।

2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा हस्ताक्षरित न्यू स्टार्ट संधि, दोनों परमाणु शक्तियों के बीच अंतिम सक्रिय हथियार नियंत्रण समझौता है। यह फरवरी 2011 में लागू हुआ और 2021 में इसे 5 फरवरी, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस समझौते का उद्देश्य सामरिक आक्रामक हथियारों को कम करना और सीमित करना था, जिससे वाशिंगटन और मॉस्को के बीच परमाणु संबंधों में स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। दोनों पक्ष 1, 550 से अधिक सामरिक परमाणु हथियार तैनात नहीं कर सकते। संधि में तैनात अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों, पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु-सक्षम भारी बमवर्षकों की संख्या 700 तक सीमित है, जबकि तैनात और गैर-तैनात लांचरों की संयुक्त संख्या 800 तक सीमित है। इन प्रतिबंधों को साइट पर निरीक्षण, नियमित डेटा आदान-प्रदान और अधिसूचनाओं जैसे विस्तृत सत्यापन उपायों द्वारा समर्थित किया जाता है, जो सभी पारदर्शिता प्रदान करते हैं और आपसी विश्वास का निर्माण करते हैं।

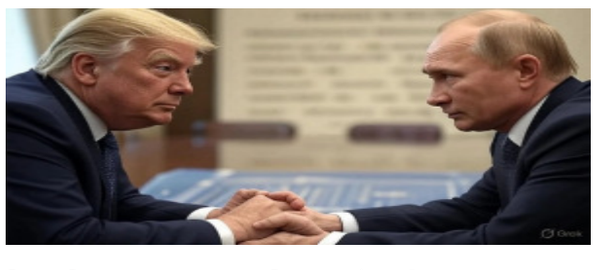

वर्तमान में वाशिंगटन और मॉस्को के बीच शेष बचा अंतिम हथियार नियंत्रण समझौता है जो सामरिक परमाणु हथियारों और संबंधित वितरण प्रणालियों पर बाध्यकारी संख्यात्मक सीमाएँ लगाता है। यह रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने, पूर्वानुमान प्रदान करने और परमाणु वृद्धि के जोखिमों को कम करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना कर रहा है। फरवरी 2023 में, रूस ने निरीक्षण और रिपोर्टिंग में अपनी भागीदारी निलंबित कर दी, हालाँकि उसने कहा कि वह संख्यात्मक सीमाओं का सम्मान करना जारी रखेगा। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर यह संधि फरवरी 2026 में बिना किसी प्रतिस्थापन के समाप्त हो जाती है, तो दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियाँ दशकों में पहली बार अपने शस्त्रागार पर किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबंध के बिना रह जाएँगी। उनका तर्क है कि ऐसा परिणाम परमाणु जोखिम बढ़ा सकता है, अविश्वास को बढ़ा सकता है और वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर सकता है।

अमेरिका पर भारत का सबसे तगड़ा हमला तेजस में अब लगेगा फ्रांस का इंजन?

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि आई हैव गॉट ऑल द कार्ड्स यानी सारे पत्ते मेरे पास हैं। लेकिन अब दुनिया भी देख रही है कि भारत ने भी अपना असली ट्रंप कार्ड खेल दिया है। खबर ये है कि भारत फ्रांस की साफरन कंपनी के उस ऑफर पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए पूरी तरह मेड इन इंडिया इंजन बनाने की पेशकश कर रहे हैं। यानी की अब अमेरिकी जीईएफ इंजन के कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यही वो चाल है जिसने अमेरिका को सकते में डाल दिया है और फ्रांस को गुपचुप तरीके से बड़ी वापसी का मौका दे दिया है।

आपको बता दें कि फ्रेंच एयरोस्पेस जाइंट साफरन ने भारत सरकार और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को ऑफर दिया है कि तेजस मार्क 2 के लिए वे एक बिल्कुल नया इंजन बनाएंगे। जिसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। सिर्फ इतना ही नहीं साफरन ने साफ

कहा कि वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देंगे। यानी इंजन की पूरी कोर टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती है। वो टेक्नोलॉजी जिसे अमेरिका आज तक किसी को आसानी से नहीं दे सकता है। आपको बता दें कि साफरान पहले से ही भारत के साथ काम कर रहा है। डीआरडीओ-जीटीआरई के साथ मिलकर 120 केएन का अगली पीढ़ी का इंजन विकसित करने का प्रोजेक्ट चल रहा है।

मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि यह 80इ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ जीई एफ414 इंजनों के सह-उत्पादन के लिए 2023 में हस्ताक्षरित मौजूदा समझौता ज्ञापन को रद्द करने का संकेत नहीं है, हालाँकि सितंबर 2025 तक वाणिज्यिक वार्ताएँ जारी हैं, और 99 इंजनों के लिए अभी तक कोई अंतिम हस्ताक्षरित सौदा या निर्दिष्ट मूल्य की पुष्टि नहीं हुई है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि व्यापक भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के संदर्भ में सफ्रान के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। अमेरिकी निर्यात नियंत्रण और प्रमाणन संबंधी मुद्दों से तनाव पैदा हो गया है, जिसका असर भारतीय वायु सेना में तेजस एमके-1ए जेट विमानों के समय पर शामिल होने पर पड़ रहा है।

लड़ाकू स्क्वाड्रनों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना का लक्ष्य एचएएल के साथ 48, 000 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत 83 तेजस एमके-1ए विमान शामिल करना है। सफल हथियार परीक्षणों के आधार पर, पहले दो उन्नत एमके-1ए जेट अगले महीने आने की उम्मीद है। इस बीच, सफ्रान की पहल भारत में अपनी मौजूदा उपस्थिति को और मज़बूत करेगी, जिसमें 2026 तक हैदराबाद में राफेल इंजनों के लिए एक एमआरओ सुविधा स्थापित करने की योजना भी शामिल है।

ट्रंप के एच-1बी वीजा का चीन ने निकाला तोड़, जिनपिंग लेकर आए 'के वीज़ा' प्लान

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा की फीस बढ़ाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ ही, चीन भी इसकी काट को निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ड्रैगन की तरफ से एक नई 'के वीज़ा' श्रेणी शुरू की है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इसके ज़रिए चीनी सरकार का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) के क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। चीन ने अगस्त में 'के वीज़ा' श्रेणी को मंज़ूरी दी थी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उस समय चीनी सरकार ने कहा था कि चीन के विकास के लिए दुनिया भर की प्रतिभाओं की भागीदारी ज़रूरी है, और चीन का विकास उन्हें अवसर भी प्रदान करता है।

के वीज़ा उन विदेशी युवा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभाओं के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने चीन या विदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्टेम क्षेत्रों में स्नातक किया है। इसके अलावा, चीनी सरकार के अनुसार, ऐसे संस्थानों में पढ़ाने या शोध करने वाले लोग भी के वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने कहा, इस निर्णय का उद्देश्य नए युग में चीन की कार्यबल विकास रणनीति को और अधिक लागू करना, विदेशी युवा विज्ञान-तकनीक प्रतिभाओं के लिए चीन में प्रवेश को सुगम बनाना और युवा विज्ञान-तकनीक पेशेवरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

चीन ने 75 देशों के साथ पारस्परिक और एकतरफा वीज़ा-मुक्ति समझौते किए हैं। राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन का हवाला देते हुए, ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि इस साल जून तक 38.05 मिलियन विदेशी नागरिकों ने चीन की या वहाँ से यात्राएँ कीं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 30.2 प्रतिशत अधिक है। इसमें 13.64 मिलियन वीज़ा-मुक्त प्रवेश शामिल थे।

जयशंकर ने फिलीपीन की विदेश मंत्री टेस लाजारो से मुलाकात की

न्यूयॉर्क **(एजेंसी)**। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां फिलीपीन की विदेश मंत्री टेस लाजारो से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की उच्चस्तरीय बैठक के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे जयशंकर ने कहा कि वह यूएनजीए के दौरान लाजारो से मिलकर प्रसन्न हैं।

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, हमने फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की हालिया भारत यात्रा पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे सहयोग पर भी चर्चा की।

लाजारो ने कहा कि जयशंकर के साथ उनकी चर्चा राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री समेत अन्य क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग विकसित करने के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में हमारे दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ रक्षा, व्यापार और निवेश, कृषि, पर्यटन और दवा उद्योग में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत के लिए भारत का दौरा किया था।

दोस्ती और समुद्र सुरक्षा पर चर्चा श्रीलंका की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी

कोलंबो **(एजेंसी)**। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर तक श्रीलंका की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए, जिसका मुख्य उद्देश्य नौसेना सहयोग को बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोगात्मक पहल को बढ़ावा देना था। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जिसमें नौसैनिक सहयोग बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोगी पहल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और वाइस एडमिरल कंचना बनगोडा से मुलाकात करेंगे और तीनों सेनाओं के प्रमुखों तथा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ रक्षा सहयोग के व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण और सहयोग को मजबूत करने के अवसरों की पहचान पर ज़ोर दिया जाएगा। वह कोलंबो में 'बदलती गतिशीलता के तहत हिंद महासागर का समुद्री परिदृश्य' विषय पर आयोजित होने वाले 12वें गैले डायलॉग 2025 - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय नौसेना वार्षिक रक्षा वार्ता, स्टाफ वार्ता और अन्य परिचालनात्मक बातचीत के माध्यम से श्रीलंकाई नौसेना के साथ नियमित रूप से बातचीत करती है, जिसमें श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास, जलमार्ग अभ्यास, प्रशिक्षण और हाइड्रोग्राफी आदान-प्रदान शामिल हैं। इसके अलावा, दोनों नौसेनाएँ नियमित रूप से हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, गाले संवाद, मिलन, गोवा समुद्री सम्मेलन/संगोष्ठी, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेती हैं।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063787346044 | Twitter: https://twitter.com/mantrabharat?t=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 | Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. UPHIN/2012/52437 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा श्री बालाजी प्रिंटर्स टिकरी, कमला नगर, प्रयागराज से मुद्रित एवं 80-ए मेहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 से प्रकाशित एवं सम्पादित।
● सम्पादक विनीता शर्मा ● मोबाइल : 9415975437, 7007837917, 9415223357 ● E-Mail : editormantrabharat@gmail.com ● वैधानिक सूचनाः- मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र प्रयागराज न्यायालय होगा।